छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 217 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 22 अगस्त 2026 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

एनएच-43 मौत का रास्ता बना, सिंहदेव ने गडकरी को लिखा पत्र

बरसात में जलभराव से आमजन परेशान, तत्काल पुनर्निर्माण कराने की मांग

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा की जीवनरेखा कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-43 की हालत बद से बदतर हो गई है। गड्ढे, टूटी सड़क और जलभराव के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस समस्या को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टी.एस. सिंहदेव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर एनएच-43 में अंबिकापुर खंड के तत्काल पुनर्निर्माण की मांग की है।

टीएस सिंहदेव ने 21 अगस्त को प्रेषित किए गए पत्र में लिखा है कि एनएच-43 का अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अंबिकापुर शहर और

अंबिकापुर शहर से दरिमा रोड तक का हिस्सा पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस सड़क पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं और सड़क के काफी हिस्से पूरी तरह टूट चुके हैं। मानसून में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण गंभीर जलभराव हो जाता है, जिससे वाहनों और पैदल चलने वालों का आवागमन अत्यंत कठिन और असुरक्षित हो गया है। पिछले करीब 3 सालों से अंबिकापुर के नागरिक इस समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क की खराब स्थिति के कारण लगातार दुर्घटनाएं और अन्य अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, जिससे क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय से असुविधा झेलने के बाद भी अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।

गडकरी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग-सड़क के महत्व और जनता की कठिनाइयों को देखते हुए टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किया है कि वे इस मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को एनएच-43 के इस हिस्से के तत्काल निर्माण और उचित जल निकासी व्यवस्था के निर्देश जारी करें। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके त्वरित हस्तक्षेप से अंबिकापुर की जनता को इस लंबित समस्या से बहुत जरूरी राहत मिलेगी। सिंहदेव ने बताया है कि मानसून के कारण सड़क की स्थिति और भी खराब हो गई है।

सरगुजा के लिए एनएच-43 है महत्वपूर्ण-बता दें कि, एनएच-43 सरगुजा संभाग को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। रोजाना हजारों वाहन, एंबुलेंस, स्कूल बसें और मालवाहक इसी सड़क से गुजरते हैं। बरसात में यह सड़क तालाब बन जाती है और गर्मी में धूल से लोग परेशान रहते हैं। एंबुलेंस, स्कूल बस और मालवाहक वाहनों को भी इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जिससे समय पर मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और बच्चों के स्कूल जाने में दिक्कत होती है। सड़क की जर्जर हालत से न सिर्फ आमजन परेशान हैं बल्कि आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं।

अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन सप्ताह में 3-4 दिन चलाया जाए

एक अन्य पत्र में पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सरगुजा संभाग के लाखों यात्रियों की सुविधा को लेकर केंद्र सरकार से अंबिकापुर-दिल्ली ट्रेन को सप्ताह में 3-4 दिन चलाने की मांग की है। केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखकर अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन सुपर फास्ट एक्सप्रेस 22407/22408 के फेरों को सप्ताह में 3-4 दिन या प्रतिदिन करने का आग्रह किया गया है।

सिंहदेव ने पत्र में उल्लेख किया है कि, वर्तमान में अंबिकापुर से दिल्ली के लिए एकमात्र सीधी ट्रेन सप्ताह में केवल गुरुवार को ही संचालित हो रही है। सरगुजा संभाग के मुख्यालय अंबिकापुर और आसपास के आदिवासी बहुल क्षेत्रों से राजधानी दिल्ली जाने वाले यात्रियों, विद्यार्थियों, गंभीर बीमार मरीजों, पर्यटकों और व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ट्रेन के एक दिन ही चलने के कारण सीटों पर लंबी वेटिंग रहती है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि यदि इस ट्रेन का संचालन सप्ताह में 3-4 दिन या प्रतिदिन किया जाए तो न केवल क्षेत्रवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। सिंहदेव ने इसे जनहित और क्षेत्र की भौगोलिक आवश्यकता बताते हुए रेल मंत्री से मामले में सकारात्मक पहल करने का अनुरोध किया है। सरगुजा से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की मांग वर्षों से की जा रही है। सांसद, विधायक और सामाजिक संगठन भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब पूर्व डिप्टी सीएम के पत्र के बाद एक बार फिर इस मांग ने जोर पकड़ा है।

जहां जल स्त्रोत उपलब्ध है, वहां शत-प्रतिशत जल प्रदाय सुनिश्चित करें-कलेक्टर

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन अजीत वसंत ने शुक्रवार को जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित एकल ग्राम योजना और समूह जल प्रदाय योजना के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी और संबंधित ठेकेदार उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने योजनावार प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन योजनाओं में जल स्रोत उपलब्ध हैं और आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें प्राथमिकता से चालू कर ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जिन ठेकेदारों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनका भुगतान समय-सीमा में किया जाए। कलेक्टर ने कहा भुगतान नहीं करने पर विभाग पर कार्रवाई की जाएगी।

भौतिक सत्यापन और गुणवत्ता पर जोर-कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वहां विभागीय अधिकारी और संबंधित ठेकेदार संयुक्त रूप से मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करें। सत्यापन के दौरान कार्य की गुणवत्ता और निर्धारित मापदंडों की जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीणों को मिल सके।

लंबित बिल और पुरानी स्कीम पर समीक्षा-बैठक में लंबित बिलों की भी समीक्षा हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित बिल एक माह के भीतर पोर्टल पर अपलोड करने और पूर्ण कार्यों की नियमानुसार जांच कर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी स्कीम के तहत बचे हुए कार्यों को भी तत्काल शुरू करने को कहा। कार्यों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने या गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई होगी, कलेक्टर ने चेतावनी दी।

ग्रामीणों तक पेयजल पहुंचाना प्राथमिकता-कलेक्टर ने अधिकारियों और ठेकेदारों को जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने के साथ गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अधिकारी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करें और मैदानी स्तर पर प्रगति की सतत समीक्षा करते हुए समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

सीजीएमएससी की लापरवाही से अस्पताल का मेडिकल आईसीयू खतरे में

सीपेज से मरीजों और उपकरणों को बचाने तिरपाल का सहारा लेना पड़ा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल के मेडिकल आईसीयू की छत में पानी के ठहराव की स्थिति बनने के बाद मरीजों और उपकरणों को बचाने के लिए तिरपाल का सहारा लिया गया है। पानी से आईसीयू में नमी और सीलन जैसी स्थिति बन गई है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। इस संवेदनशील जगह को पानी से बचाने की पहल की जानी थी, लेकिन सीजीएमएससी की हीलाहवाली से हालात में समय रहते सुधार नहीं हो पाया है, और हाल में टेंडर की बात सामने आ रही है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, पिछले दिनों हुई लगातार रही बारिश के बाद मेडिकल आईसीयू की छत में जगह-जगह पानी भर गया था। छत से सीपेज होकर पानी बेड और वेंटिलेटर के पास तक न पहुंचे, इससे बचाव के लिए यह पहल की गई है। स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने आनन-फानन में आईसीयू के ऊपर तिरपाल लगवा दिया, ताकि पानी के सीपेज का प्रभाव अंदर तक न आने पाए, और मरीजों को सुरक्षित रखा जा सके। बता दें कि, मेडिकल आईसीयू में गंभीर मरीज भर्ती रहते हैं। यहां वेंटिलेटर, मॉनिटर और अन्य महंगे उपकरण लगे हुए हैं। छत से पानी टपकने से उपकरण खराब होने और शॉर्ट-सर्किट का डर भी बना रहता है। अस्पताल की सबसे संवेदनशील यूनिट की यह हालत चिंता का विषय है। करीब 3 वर्ष पूर्व यहां छत में लगे फाल्स सीलिंग भी पानी की नमी में गिर गया

था, इसके बाद तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक ने भी ऊपर से शेड लगाने की जरूरत महसूस की थी।

अस्पताल के चिकित्सक भी दबे जुबां स्वीकार कर रहे हैं कि, आईसीयू जैसे वार्ड में नमी और सीलन से संक्रमण का खतरा संभावित है। ऐसे में आईसीयू वार्डों में बारिश के समय ऐसे हालात न बनें, इसके लिए स्थायी समाधान की जरूरत है। हालांकि जर्जर हो चुके पुराने अस्पताल भवन में तमाम कोशिशों के बाद भी हालिया बारिश में जगह-जगह पानी टपकने और बिजली के बोर्ड तक तर रहना सामने आ चुका है। देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का स्थायी निदान कब तक करता है।

सीजीएमएससी ने किया है टेंडर -आईसीयू के प्रभारी डॉ. अर्पण सिंह ने बताया कि, मेडिकल आईसीयू के छत में पानी का जमाव हो रहा था, इसे देखते हुए तिरपाल लगाया गया है। वर्तमान कलेक्टर के संज्ञान में भी इसे लाया गया है। कलेक्टर ने सीजीएमएससी को आवश्यक कार्रवाई करने कहा गया है। सीजीएमएससी के द्वारा भरी बरसात में 15 दिन पहले टेंडर की बात सामने आई है।

ऑटो में दबे सवार की हुई पहचान, स्वजन को सौंपा शव

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कार की ठोकर से मृत ऑटो सवार की पहचान उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंडरी भंडारडांड निवासी कवल साय अगरिया 65 वर्ष के रूप में हुई है। हादसा 19 अगस्त की शाम को करीब 7 बजे डांडगांव के देवलला मोड़ के पास हुआ था। बताया जा रहा है कि, ऑटो सवार कवल साय अन्य सवारियों के साथ जा रहा था, इसी दौरान कार वाहन के चालक ने ऑटो को ठोकर मार दिया, जिसमें ऑटो पलट गई और वह ऑटो के नीचे दब गया था। अन्य को सामान्य चोटें आई थी। घायल कंवल साय को उदयपुर स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक उपचार के बाद रिफर करने पर एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर भेजा गया, यहां जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथ किसी संबंधी के नहीं रहने के कारण पुलिस ने शव को मर्च्युरी में रखवा दिया था। गुरूवार की शाम को मृतक के संबंधियों को इसका पता चला और वे अंबिकापुर पहुंचे। शुक्रवार को शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने इनके सुपुर्द कर दिया है।

डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, हर क्लिक से पहले सोचें

मोंटफोर्ट स्कूल के विद्यार्थियों को साइबर और यातायात सुरक्षा की शिक्षा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। साइबर जागृति अभियान के तहत गुरुवार को मोंटफोर्ट स्कूल, अंबिकापुर में विद्यार्थियों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक ने छात्रों को साइबर ठगी, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों की बारीकियां समझाईं।

मुख्य वक्ता नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल ने विद्यार्थियों को बढ़ते साइबर अपराधों से बचने के तरीके बताए। उन्होंने अनजान नंबर से आने वाली कॉल, संदिग्ध लिंक, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल और ऑनलाइन पेमेंट के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया में थोड़ी सी लापरवाही आपको ठगी का शिकार बना सकती है, इसलिए हर क्लिक से पहले सोचें। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य ब्रदर एस. गेब्रियल, कोऑर्डिनेटर ममता तिवारी, संगीता पाण्डेय, सिस्टर निशा रानी, पूजा गुप्ता, कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर नितिन कर्ष और मंच संचालिका मनदीप भामरा उपस्थित रहीं। महिला थाना से महिला आरक्षक सविता मरावी, लोरेता एक्का, संगीता बड़ा, पुलिस मितान टीम और साइबर वॉलंटियर भार्गवी द्विवेदी, अतुल गुप्ता, विक्की गुप्ता, विकेश राजवाड़े भी मौजूद थे।

1930 हेल्पलाइन और अभिव्यक्ति ऐप

महिला थाना प्रभारी उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज ने छात्र-छात्राओं को साइबर और महिला सुरक्षा से जुड़े हेल्पलाइन नंबर बताए। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन 1930 के बारे में बताया और 'जागरूकता की एक सेल्फी' अभियान के क्यू आर से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप के उपयोग की जानकारी भी दी।

हेलमेट-सीट बेल्ट और नो मोबाइल का संदेश

यातायात प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त ने सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि, दोपहिया चलाते समय हेलमेट, कार में सीट बेल्ट अनिवार्य है। यातायात संकेतों का पालन करें और वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल न करें। विद्यार्थियों ने साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा और यातायात नियमों पर सवाल पूछे। अंत में 'जागरूकता ही सुरक्षित समाज की मजबूत नींव है' संदेश के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।

पांच स्कूल के 1000 छात्रों को सिखाया ठगी से बचने का फॉर्मूला

डीआईजी/एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नोडल अधिकारी साइबर सेल रितेश चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को 5 शिक्षण संस्थानों में एक साथ 'साइबर जागृति अभियान' आयोजित किए गए। केदमा हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल बरगीडीह, उर्सुलाइन हिंदी मीडियम स्कूल, मेंड्राकला हाई स्कूल और शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर में छात्रों, छात्राओं और नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में पुलिस टीम ने युवाओं को आजकल बढ़ रहे साइबर अपराधों और ठगी के नए तरीकों के बारे में बताया, और ऐसे अपराधों से बचने के उपाय समझाए। सोशल मीडिया पर निजी फोटो-वीडियो डालने में भी सावधानी बरतने कहा। इस दौरान उर्सुलाइन स्कूल की प्राचार्या रेजिना लकड़ा, नवा बिहान टीम से अजय तिवारी, मंगल पाण्डेय, निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, उप निरीक्षक अश्वनी दीवान, अभय तिवारी, प्रशिक्षु उप निरीक्षक हर्ष कुमार, एएसआई अनिल पाण्डेय, राहुल केरकेट्टा, दशरथ राजवाड़े सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

'महज 70 रुपये बकाया के लिए चाकू से ताबड़तोड़ हमला'

पिता-पुत्र पर घटना को अंजाम देने का आरोप, तीन घायल हुए

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शहर के सुभाषनगर में महज 70 रुपये बकाया को लेकर गुरुवार की रात खूनी खेल हो गया। उधार मांगने पहुंचे युवक और उसके दोस्त पर चखना सेंटर संचालक पिता-पुत्र ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में तीन लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक, शहर के हर्षित चक्रवर्ती 32 वर्ष की दुकान से सुभाषनगर का बबलू ढाली पिता सदानंद ढाली ने कुछ दिन पहले सामान खरीदा था, जिसका 70 रुपये बकाया रह गया था। बबलू सुभाषनगर स्थित शासकीय शराब दुकान के पास चखना सेंटर चलाता है। गुरुवार रात करीब 8 बजे हर्षित अपने दोस्त राहुल पटेल के साथ बकाया मांगने चखना सेंटर पहुंचा। रुपये मांगते ही विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि इसी बीच बबलू और उसके पिता ने जेब से चाकू निकालकर हर्षित पर हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए राहुल के गले पर भी चाकू से वार कर दिया। चाकू के वार से हर्षित के चेहरे, ठुड्डी, हाथ और जांघ में गहरे घाव हो गए। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने किसी तरह दोनों हमलावरों को रोका और पुलिस को घटना की सूचना दी। घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि, हर्षित को निजी अस्पताल में भर्ती किया गया जहां डॉक्टरों ने उसे 41 टांके लगाए गए, वहीं राहुल पटेल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 20 टांका लगाया गया है। दोनों की हालत अब खतरे से बाहर है।

पुलिस ने दर्ज किया केस-घायलों की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी पिता-पुत्र बबलू ढाली और सदानंद ढाली के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिर्फ 70 रुपये के लिए हुई चाकूबाजी की घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है।

सखी निवास योजना के रिक्त पदों हेतु पात्र-अपात्र सूची जारी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना के संचालन हेतु जिले में सेवाप्रदाता के स्वीकृत 05 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की पात्र-अपात्र सूची जारी कर दी गई है। जारी सूची के अनुसार प्रबंधक का 01 पद, वार्डन का 01 पद तथा केयर टेकर के 03 पद शामिल हैं। आवेदक पात्र-अपात्र सूची का अवलोकन कर सकते हैं तथा यदि किसी आवेदक को सूची के संबंध में कोई दावा-आपत्ति हो तो वह निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति 31 अगस्त को कार्यालयीन समय शाम 5.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकता है। सूची का अवलोकन सरगुजा जिले की वेबसाइट तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय के सूचना पटल पर किया जा सकता है।

के आर टेक्निकल कॉलेज
SINCE 2008
(Regular | Private | Distance)
ADMISSION OPEN 2026-27
मान्यताएँ
संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से सम्बद्ध
छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त
इग्नू का स्टडी सेंटर
SINCE 2008
COURSES OFFERED
UG COURSES: BCA, BBA, BCOM, BSC BIO, BSC MATHS, BSC CS, BA
PG COURSES: MSC CS, MSC IT, MSC BOTANY, MSC ZOOLOGY, MSC CHEMISTRY, MSC MATHS, MSC PHYSICS, MCOM, MSW, MA HINDI
PROFESSIONAL COURSES: DCA, PGDCA, PGDBM, PGDRD, BLIB
SCHOLARSHIP FACILITIES
विद्यासागर छात्रवृत्ति (सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए)
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC, ST एवं OBC विद्यार्थियों हेतु)
सीमित कोर्स में फ्री कोचिंग सुविधा उपलब्ध
COLLEGE CAMPUS: अम्बिकापुर रेलवे स्टेशन के पास, काली घाट मंदिर के आगे, संजय नगर, छत्तीसगढ़
9926513170, 9826612781
CITY OFFICE: कृष्ण आभा भवन, रिंग रोड, नमना कला, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़
9826183771

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026
ISO 9001: 2015 CERTIFIED
बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।
डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद
समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा
बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

आरक्षक भर्ती का झांसा देकर 12 लाख ठगे, दो आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग, 21 अगस्त। वर्ष 2023 में पुलिस आरक्षक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 12 लाख रुपये की ठगी करने वाले दो आरोपियों को उतई थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। आरोपियों के कब्जे से मामले से जुड़े बैंक खाते और एक मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) एवं 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। ग्राम सेलूद निवासी गैंदलाल बंछोर ने थाना उतई में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2023 में आरोपी उमेश दास मानिकपुरी ने उसके पुत्र विकास बंछोर को पुलिस आरक्षक के पद पर भर्ती कराने का भरोसा दिलाया था। इसके बाद अपने सहयोगी राजेश वर्मा के साथ मिलकर अलग-अलग किश्तों में कुल 12 लाख रुपये ले लिए। काफी समय बीतने के बाद भी न तो नौकरी मिली और न ही रकम वापस की गई। खुद को ठगा महसूस करने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने बैंक लेन-देन, दस्तावेजों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। पर्याप्त प्रमाण मिलने पर थाना उतई की टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान प्रकरण से संबंधित बैंक खाता और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक श्रीराम पेन्द्रो, प्रधान आरक्षक मनीष थापा, अभिषेक पाण्डेय, आरक्षक ध्रुवनारायण चन्द्राकर, अजय देवांगन सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

भारी बारिश में खुद बदहाल हुआ नगर पंचायत भवन, छत से गिर रहा प्लास्टर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। नगरवासियों को सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संभालने वाला नगर पंचायत बिश्रामपुर भवन इन दिनों खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहाती नजर आ रहा है। गौरतलब है कि करीब 14 वर्ष पहले निर्मित नगर पंचायत भवन बारिश के मौसम में जर्जर हालत का सामना कर रहा है। भवन की छत से जगह-जगह प्लास्टर गिरने लगा है, वहीं छत में सीपेज की समस्या के कारण कार्यालयीन कार्य प्रभावित होने के साथ कर्मचारियों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश शुरू होते ही भवन की हालत और अधिक खराब नजर आने लगी है। छत से पानी रिसने के कारण कई हिस्सों में नमी बनी हुई है और प्लास्टर कमजोर होकर गिर रहा है। इससे कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंचने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है। यदि समय रहते क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत नहीं कराई गई तो बारिश के दौरान प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिरने से दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ज्ञात हो कि नगर पंचायत बिश्रामपुर भवन में प्रतिदिन लोग विभिन्न कार्यों को लेकर पहुंचते हैं। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, कर संबंधी कार्य, सफाई एवं पेयजल संबंधी शिकायतें, निर्माण कार्यों सहित अन्य नागरिक सेवाओं के लिए लोगों की आवाजाही बनी रहती है। ऐसे में भवन की जर्जर स्थिति नगर पंचायत की कार्यप्रणाली और आने वाले नागरिकों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है। विडंबना यह है कि नगर पंचायत प्रबंधन शहरवासियों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं तैयार करता है, लेकिन जिस भवन से इन सेवाओं का संचालन होता है, वही भवन बारिश में अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। नगर पंचायत प्रबंधन की ओर से भवन में सुधार कार्य कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सीपेज और छत के क्षतिग्रस्त हिस्सों की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक सुधार कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। लोगों ने नगर पंचायत भवन की स्थिति को देखते हुए छत की तकनीकी जांच कराने, सीपेज की स्थायी रोकथाम करने तथा जहां-जहां प्लास्टर कमजोर हो चुका है, वहां तत्काल मरम्मत कराने की मांग की है।

लोगों का कहना है कि शहर की समस्याओं का समाधान करने वाले नगर पंचायत भवन को ही यदि सुरक्षित और व्यवस्थित नहीं रखा गया तो नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का संदेश अधूरा रह जाएगा। फिलहाल बारिश के मौसम में नगर पंचायत भवन की बदहाल तस्वीर व्यवस्था के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि शहर की देखरेख करने वाली संस्था का अपना आशियाना ही कब तक बदहाली की मार झेलता रहेगा।

लाखों के उर्वरक घोटाले में एक माह बाद भी एफआईआर नहीं

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जयनगर में सामने आए करीब 75 लाख रुपए के उर्वरक घोटाले के मामले में जांच रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद एक माह बाद भी दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। इससे मामले में लीपापोती की आशंका के साथ कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि खरीफ सीजन में जयनगर समिति से किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश पर सहकारिता विभाग की टीम ने गत माह समिति पहुंचकर जांच शुरू की। इस दौरान तत्कालीन समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति को उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन उपपंजीयक द्वारा बार-बार संपर्क किए जाने के बावजूद वह जांच में उपस्थित नहीं हुआ। गड़बड़ी की आशंका के चलते समिति के स्टॉक रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेजों को जब्त कर बारीकी से जांच की गई। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद उपपंजीयक ने समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति को निलंबित कर दिया था। मामले की जांच के दायरे में आए विपणन संघ के डबल लॉक गोदाम प्रभारी लिवेन खेस को भी निलंबित किया गया था। मामले की विस्तृत जांच के लिए उपपंजीयक ने तीन सदस्यीय सहकारिता निरीक्षकों की टीम गठित की थी। सहकारिता निरीक्षक जॉन केरकेट्टा, महेंद्र राजवाड़े और नवीन सिंह की टीम ने जांच के दौरान स्टॉक का मिलान किया, जिसमें करीब 75 लाख रुपए का उर्वरक स्टॉक कम पाया गया। साथ में पीओएस मशीन और स्टॉक पंजी सहित आनलाइन इंट्री में भी व्यापक हेराफेरी पाई गई, जिससे कुल गड़बड़ी 75 लाख रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट उपपंजीयक को सौंप दी है। बावजूद इसके अब तक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने से कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

85 लाख के धान घोटाले के बाद फिर सुर्खियों में समिति

जयनगर समिति में सामने आई यह गड़बड़ी इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि समिति प्रबंधक श्यामलाल प्रजापति का नाम करीब पांच वर्ष पूर्व 85 लाख रुपए के धान की कथित अफरा-तफरी के मामले में भी जुड़ा था। उस समय कुछ अवधि के लिए निलंबन के बाद उसकी बहाली कर दी गई थी। अब एक बार फिर उसके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर उर्वरक स्टॉक में कमी सामने आने से सवाल उठ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि किसानों को खरीफ और रबी सीजन में वितरित किए जाने वाले उर्वरक को बिचौलियों के माध्यम से खुले बाजार में खपाने का खेल किया गया। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कथित गड़बड़ी में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही समिति प्रबंधक के पूरे पदस्थापना काल की जांच की मांग भी क्षेत्रवासियों ने की है।

सूरजपुर जिले में आठ निरीक्षकों की नवीन पदस्थापना

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश से निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की कमी से जूझ रहे सूरजपुर जिले को आठ निरीक्षक मिले हैं। जारी आदेश में प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में पदस्थ 35 निरीक्षकों का तबादला कर उन्हें दूसरे जिलों में पदस्थ किया गया है। सूरजपुर जिले में पदस्थ निरीक्षकों में रंजीत प्रताप सिंह को सुकमा से सूरजपुर, राजनांदगांव जिले में पदस्थ राजेश साहू, पुरूषोतम लाल, सत्यनारायण देवांगन, मिलन सिंह, नंदकिशोर गौतम, रमेश कुमार पटेल, ढाल सिंह साहू को सूरजपुर जिले में पदस्थापना दी गई है। आठ निरीक्षक स्तर के अधिकारियों की पदस्थापना से जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है।

मंत्री लक्ष्मी ने प्रभार जिला की ली विभागीय समीक्षा बैठक योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने दिए निर्देश

निर्माणाधीन स्कूल भवनों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश हर घर मुनगा रोपण पर जोर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलरामपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और विकास कार्यों का प्रभाव मैदानी स्तर पर दिखाई देना चाहिए। अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी के लिए मैदानी क्षेत्रों में जाएं तथा कार्यों में गुणवत्ता और गति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से ही क्षेत्र का समग्र विकास संभव है। सभी विभाग अपने दायित्वों का प्रभावी निर्वहन करते हुए निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें।

मंत्री राजवाड़े ने यह निर्देश संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।

बैठक में मंत्री राजवाड़े ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों, अविवादित एवं विवादित खाता विभाजन, सीमांकन तथा एग्रीस्टेक पंजीयन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने किसानों का एग्रीस्टेक एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि कोई पात्र किसान शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। खाद-बीज के भंडारण एवं वितरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने तथा वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए।

मुनगा बनेगा पोषण का आधार

मंत्री ने आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण वृक्ष मुनगा के रोपण की जानकारी लेते हुए हर घर मुनगा वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुनगा पौष्टिकता का अच्छा स्रोत है, इसलिए इसे पोषण अभियान से जोड़कर अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाया जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को जैविक खेती एवं सब्जी उत्पादन से जोड़ने पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया, ताकि महिलाओं की आय बढ़ने के साथ परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार हो।

स्कूल भवनों की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा पर जोर

स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री राजवाड़े ने निर्माणाधीन स्कूल भवनों में गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने तथा मरम्मत योग्य भवनों की समय पर मरम्मत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने न्योता भोज के माध्यम से विद्यार्थियों को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने तथा आश्रम-छात्रावासों में भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया। स्कूलों में सामुदायिक शौचालयों में पर्याप्त पानी, साफ-सफाई एवं समुचित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की समीक्षा की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, खराब हैंडपंपों का तत्काल सुधार तथा जलस्रोतों के संरक्षण एवं जलसंचय कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा।

स्वास्थ्य एवं पशुपालन योजनाओं की भी समीक्षा

स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने जिला चिकित्सालय में साफ-सफाई एवं आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग की समीक्षा में उन्होंने कृत्रिम गर्भाधान, पशु टीकाकरण, गौधाम योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिक से अधिक पशुपालकों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया।

राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई एवं पीएम जनमन सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने तथा नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का चिन्हांकन एवं सीमांकन कर नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा।

बैठक में कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने वर्षा एवं बोवाई की स्थिति, एग्रीस्टेक पंजीयन, वीबी-जी रामजी, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास, पीएम जनमन आवास एवं सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति से मंत्री को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने पंजीबद्ध अपराध, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, सड़क दुर्घटनाओं एवं हेलमेट जागरूकता अभियान की जानकारी दी।

वनमण्डलाधिकारी आलोक वाजपेयी ने विभागीय कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान मंत्री राजवाड़े ने हाथी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने, नियमित मुनादी कराने तथा ग्रामीणों को समय पर सचेत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाथी प्रभावित क्षेत्रों में जनहानि रोकने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। बैठक में सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, प्रतापपुर विधायक विधायक प्रतिनिधि बलवंत सिंह सहित जिले के अधिकारी उपस्थित रहे।

मदद के बहाने मोबाइल लेकर भागे, चोरी का फोन खरीदने और लॉक तोड़ने वाले दो गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

बिश्रामपुर। पेट्रोल खत्म होने के बाद मदद के लिए आगे आए दो युवकों ने पहले बाइक पर बैठाकर पेट्रोल पंप तक पहुंचाया और फिर फोन करने के बहाने मोबाइल मांगकर फरार हो गए।

जयनगर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए चोरी का मोबाइल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। जयनगर पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत ठाकुरपुर अंबिकापुर निवासी क्षितिज कुमार अपने दोस्त विशाल की स्कूटी से 29 जून 2026 को सूरजपुर में दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने आया था। पार्टी समाप्त होने के बाद दोनों स्कूटी से अंबिकापुर लौट रहे थे। इसी दौरान अजबनगर के पास स्कूटी का पेट्रोल खत्म हो गया। मजबूरी में दोनों स्कूटी को पैदल ही कालीघाट की ओर ले जाने लगे।

इसी दौरान पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां पहुंचे। उन्होंने रुककर युवकों से परेशानी के बारे में पूछा और मदद करने की बात कहते हुए पेट्रोल लेने अपने साथ चलने तथा बाद में वापस छोड़ने का भरोसा दिलाया। मदद की उम्मीद में क्षितिज उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वैष्णवी पेट्रोल पंप पहुंच गया। मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों में से एक ने कहा कि उसे फोन करना है और क्षितिज से उसका मोबाइल मांग लिया और मोटरसाइकिल पर सवार होकर मौके से फरार हो गया। मदद की उम्मीद लेकर निकले युवक के साथ इस तरह मोबाइल लूट लिए जाने से वह हक्का-बक्का रह गया।

घटना के बाद क्षितिज ने जयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसकी शिकायत पर पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 303 (2), 317 (2) एवं 3 (5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने चोरी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए थाना एवं चौकी प्रभारियों को घटनाओं की बारीकी से विवेचना कर आरोपियों तक पहुंचने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जयनगर पुलिस ने मामले में मिले सुरागों और प्राप्त सूचना के आधार पर संदेही मोहम्मद सरफराज साह पिता शोयब साह, उम्र 26 वर्ष, निवासी मायापुर, थाना कोतवाली अंबिकापुर को पकड़ा। पूछताछ के दौरान सरफराज ने चोरी का मोबाइल एक व्यक्ति से खरीदकर अपने पास रखना स्वीकार किया। उसने पुलिस को बताया कि मोबाइल का लॉक खुलवाने के लिए उसने अंबिकापुर के मोमिनपुरा निवासी सज्जाद अंसारी से संपर्क किया था। सज्जाद ने मोबाइल का लॉक तोड़ दिया, जिसके बाद सरफराज उसका इस्तेमाल कर रहा था। सरफराज की निशानदेही पर पुलिस ने मोमिनपुरा निवासी सज्जाद अंसारी पिता मोहम्मद उमर अंसारी 29 वर्ष को भी पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का मोबाइल बरामद कर लिया है। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार है। उसकी पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

पुलिस की इस कार्रवाई से यह भी सामने आया कि चोरी किए गए मोबाइल को खपाने के साथ उसका लॉक तोड़कर इस्तेमाल में लाने की कोशिश की गई थी।कार्रवाई में जयनगर थाना प्रभारी अमित गुप्ता, प्रधान आरक्षक दीपक दुबे, सुशील तिवारी, आरक्षक सुरेश साहू एवं अम्बिका मरावी सक्रिय रहे।

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)

रा०प्र०क्र० / 20(1) / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका रणविजय सिंह तोमर आ० / पति चन्द्रिका सिंह तोमर जाति, निवासी दर्रीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला–पोस्ट ऑफिस रोड़, शीट नम्बर–10 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 4016 / 2 रकबा 0.07: एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 07.09.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 24.07.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। आकांक्षी विकासखंड लखनपुर में फेमेक्स कार्यक्रम 2026-27 के अंतर्गत 'आपदा से तैयारी - है समझदारी' एवं 'सजग नागरिक - सुरक्षित समाज' की थीम पर आपदा प्रबंधन एवं जन-जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन जनपद पंचायत सभाकक्ष में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान जन-धन की सुरक्षा, त्वरित बचाव एवं राहत कार्यों के प्रति जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को प्रशिक्षित करना था। कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रशिक्षण में एनडीआरएफ की टीम द्वारा जनपद क्षेत्र के सरपंचों, सचिवों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन के व्यावहारिक उपायों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान बाढ़ से बचाव, अग्निकांड की स्थिति में सुरक्षा उपाय, भूकंप के समय बरती जाने वाली सावधानियां, आकाशीय बिजली से बचाव, करंट लगने की स्थिति में प्राथमिक सहायता, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के बचाव तथा सीपीआर देने की प्रक्रिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही डूबने की स्थिति में व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने तथा प्राथमिक उपचार के संबंध में भी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में उपस्थित सरपंच एवं सचिवों ने एनडीआरएफ की टीम के साथ संवाद करते हुए अपने क्षेत्र में आने वाली आपदाओं से संबंधित समस्याएं एवं जिज्ञासाएं साझा कीं। विशेष रूप से सर्पदंश एवं आकाशीय बिजली गिरने जैसी घटनाओं के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा एवं बचाव उपायों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। एनडीआरएफ के विशेषज्ञों ने प्रत्येक स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों एवं त्वरित कार्रवाई के बारे में बिंदुवार जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को यह संदेश दिया गया कि आपदा के समय घबराने के बजाय सजगता, सही जानकारी और समय पर की गई कार्रवाई से अनेक बहुमूल्य जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शशिकला सिंह, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष कामेश्वर राजवाड़े सहित जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच एवं सचिव उपस्थित रहे।

सर्राफा एसोसिएशन ने पीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजगंज। जिले के सरार्फा एसोसिएशन ने अपनी पुश्तैनी व्यापार की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के नाम बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्यवाही की मांग की गई है। सौंपे गए ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी शोरूमों के द्वारा किए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों, आकर्षक प्रलोभनों और व्यापारिक विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहां गया है कि किसी भी संस्थान का विरोध करना नहीं बल्कि ₹वोकल फॉर लोकल₹ और ₹आत्मनिर्भर भारत₹ की भावना को मजबूत करते हुए स्थानीय सराफा व्यापारियों और कारीगरों के हितों की रक्षा करना है। साथ ही संगठन के प्रमुख मांगों में स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता और पारदर्शिता के लिए स्वतंत्र जांच की व्यवस्था, भ्रामक विज्ञापनों, सस्ता सोना, जीरो मेकिंग चार्ज पर सख्त रोक, पूरे देश के लिए समान और पारदर्शी बिलिंग व्यवस्था, स्वर्ण कारीगरों के संरक्षण हेतु स्वर्ण कल्याण बोर्ड का गठन, सरार्फा व्यापार से जुड़े कानूनी प्रावधानों का सरली करण जैसे पांच मांगे रखी गई है। आगे सरार्फा एसोसिएशन का कहना है कि स्थानीय सरार्फा व्यापारी वर्षों से विश्वास और पारदर्शिता के आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार से अपील करते हैं कि इस विषय पर सकारात्मक कदम उठाते हुए हमारे पुश्तैनी व्यापार और कारीगरों की आजीविका सुरक्षित करें। इस अवसर पर राजेश सोनी जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष, सरार्फा एसोसिएशन इकाई रामानुजगंज, रोशन लाल मणि जिला महामंत्री एवं अध्यक्ष, सरार्फा एसोसिएशन इकाई बलरामपुर, दीपक कुमार, अजय सोनी, संरक्षक सदस्य उपस्थित रहे।

कम लागत में राखी बनाकर आजीविका को नई दिशा दे रहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अब मौसम और त्योहारों के हिसाब से आजीविका अपना रही हैं। अम्बिकापुर विकासखंड के ग्राम पंचायत किशुन नगर की जय मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इसका बेहतरीन उदाहरण हैं।

रक्षाबंधन पर राखी निर्माण से आय

रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए समूह की 12 महिलाएं घर में उपलब्ध सामग्री एवं स्थानीय संसाधनों से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। समूह की सदस्य सोनाली सिंह ने बताया कि राखी बनाने में पुराने बीज, चावल, गेहूं एवं मक्के के दानों को रंगकर डिजाइन तैयार किया जाता है। साथ ही बाजार से रेशमी धागे, ऊन एवं सजावटी सामग्री खरीदी जाती है। इस तरह बहुत कम लागत में सुंदर राखियां बन जाती हैं। तैयार राखियों को बाजार में स्टॉल लगाकर और घर से भी बेचा जाता है। इससे मिलने वाली आय को महिलाएं अपनी आजीविका बढ़ाने में उपयोग कर रही हैं।

बिहान से बदली जिंदगी

समूह की सदस्य दीप्ति चौधरी ने बताया कि बिहान योजना से जुड़ने से पहले आर्थिक स्थिति कमजोर थी और आजीविका के साधन सीमित थे। समूह से जुड़ने के बाद प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिला। अब महिलाएं खाली समय में एक साथ बैठकर राखियां बनाती हैं और सीजन में मांग बढ़ने पर अधिक उत्पादन करती हैं। आशा रवि ने कहा कि पिछले 3 वर्षों से वे कम लागत में घरेलू सामग्री से राखियां बना रही हैं।

चाकू लहराकर दहशत फैलाने वाला गिरफ्तार, अवैध हथियार जब्त

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में अवैध हथियार के साथ लोगों में दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी नंदी चौक के पास धारदार चाकू लहराकर आने-जाने वाले लोगों को भयभीत कर रहा था। 21 अगस्त को टिकरापारा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नंदी चौक के पास एक युवक धारदार लोहे का चाकू लेकर घूम रहा है और राहगीरों को डराकर दहशत का माहौल बना रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मरई के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर तत्काल मौके पर घेराबंदी की गई। पुलिस ने सूझबूझ के साथ कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक धारदार लोहे का चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रजत उर्फ अभिषेक ठाकुर पिता श्याम ठाकुर, उम्र 30 वर्ष, निवासी नंदी चौक के पास टिकरापारा, थाना टिकरापारा रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 773/2026 दर्ज किया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। डीसीपी वेस्ट जोन रोबिनसन गुड़िया, एडीसीपी राहुल देव शर्मा और एसीपी न्यू राजेंद्र नगर नवनीत पाटिल के निर्देश पर शहर में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में अवैध हथियार लेकर घूमने और आम नागरिकों को डराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमना या भय का माहौल बनाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पीएम आवास में छत्तीसगढ़ का डंका, 10 महीने में 5 लाख आवास पूरे, देश में सबसे तेज रफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देशभर में नई पहचान बनाई है। राज्य ने आवास निर्माण की रफ्तार में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया है।

रिकॉर्ड रफ्तार से निर्माण

छत्तीसगढ़ ने महज 10 महीने 4 दिन में 5 लाख प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है। वर्तमान में राज्य में रोजाना 1600 से अधिक पक्के मकान पूरे किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 2025 में अप्रैल से अक्टूबर तक तो प्रतिदिन करीब 2000 आवास पूर्ण हुए थे। देश में अभी सबसे अधिक पीएम आवास रोजाना छत्तीसगढ़ में ही बन रहे हैं।

18 लाख आवास का संकल्प

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के अगले ही दिन कैबिनेट की पहली बैठक में प्रदेश के गरीबों के लिए 18 लाख आवास बनाने का संकल्प लिया था। सरकार उस संकल्प को तेजी से पूरा कर रही है। सरकार के ढाई वर्ष के कार्यकाल में अब तक 10 लाख 60 हजार से अधिक ग्रामीण आवास पूर्ण हो चुके हैं। इसके साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत वनांचलों में 33,601 और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेष परियोजना के अंतर्गत 15,000 अतिरिक्त आवास भी बनाए जा रहे हैं।

आवास प्लस 2.0 और शहरी योजना

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ₹आवास प्लस 2.0-2024₹ के अंतर्गत कच्चे घर वाले गरीबों का सर्वे कर उनके लिए भी आवास निर्माण शुरू किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत राज्य में 7,230 नए आवासों को मंजूरी मिली है। 106 नगरीय निकायों में बनने वाले इन घरों के लिए पात्र हितग्राहियों को 2.50 लाख तक की सहायता मिलेगी।

कुल 24.37 लाख आवास स्वीकृत

राज्य में पीएम आवास योजना के तहत अब तक करीब 24.37 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में आवास पूर्ण हो चुके हैं। सीएम विष्णु देव साय ने कहा, ₹हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट में प्रदेश के गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था, उसे पूरी प्रतिबद्धता से धरातल पर उतार रहे हैं। यह केवल मकानों का निर्माण नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर भविष्य की नींव है।

तालाब में डूबे दो सगे भाई, छोटे को बचाने कूदा बड़ा भी जान गंवा बैठा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार चिल्हाटी निवासी भक्त प्रहलाद पैकरा किसान हैं। गुरुवार शाम वह अपने दो बेटों दीपू पैकरा (7 वर्ष) और चींटू पैकरा (4 वर्ष) को लेकर गांव के तालाब के पास गए थे। पिता बच्चों को तालाब किनारे छोड़कर कुछ दूरी पर मोबाइल पर बात करने लगे। इसी दौरान खेलते समय 4 वर्षीय चींटू का पैर फिसल गया और वह तालाब के गहरे पानी में चला गया। डूबते हुए छोटे भाई को देखकर 7 वर्षीय दीपू उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद गया। लेकिन तालाब की गहराई अधिक होने के कारण वह भी संभल नहीं पाया और दोनों भाई डूब गए।

ग्रामीणों ने निकाला, अस्पताल में तोड़ा दम

घटना के दौरान वहां मौजूद एक युवक ने शोर मचाया। आवाज सुनकर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने तालाब में उतरकर दोनों बच्चों को बाहर निकाला और तत्काल पचपेड़ी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने दोनों को मस्तूरी अस्पताल रेफर कर दिया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया।

दो मासूम भाइयों की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों बच्चे परिवार के काफी लाड़ले थे।

पुलिस जांच जारी

सूचना मिलने पर पचपेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया।

आईजीकेवी में एंटोमोलॉजी पेपर लीक होने पर एनएसयूआई ने नोटों की माला-डायपर लेकर किया विरोध प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष ह्लफसल और भंडारित अनाज में कीट प्रबंधन-कह्व (कोर्स कोडः एईएनटी221) का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल होने और परीक्षा में वही प्रश्नपत्र आने के मामले को लेकर एनएसयूआई ने जमकर विरोध जताया।

एनएसयूआई का घेराव प्रदर्शन

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय के नेतृत्व में कार्यकताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकताओं ने नोटों की माला और डायपर लेकर प्रशासन पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए।

बार-बार पेपर लीक का आरोप

एनएसयूआई ने कहा कि आईजीकेवी में यह कोई पहला मामला नहीं है। वर्ष 2022 और 2024 में भी प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब तीसरी बार परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र वायरल हुआ है। संगठन का आरोप है कि बार-बार ऐसी घटनाएं परीक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही दशार्ती हैं और विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े करती हैं।

क्या है मांग?

पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच हो। प्रश्नपत्र किस माध्यम से वायरल हुआ इसकी जांच हो और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई हो विद्यार्थियों के हित में परीक्षा को लेकर उचित निर्णय लिया जाए।

25 अगस्त से शुरू होगा नेत्रदान पखवाड़ा, निकाली जाएगी जनजागरूकता रैली

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। शासन के निदेर्शानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले में 25 अगस्त से 08 सितम्बर तक नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। पखवाड़े के दौरान आम नागरिकों को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि नेत्रदान के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 25 अगस्त को सुबह 10 बजे जन-जागरूकता रैली निकाली जाएगी। रैली राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंह देव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय के परिसर से प्रारंभ होकर जय स्तंभ चौक, महामाया चैक होते हुए घड़ी चौक पहुंचेगी। इसके बाद रैली संगम चौक, ब्रह्म रोड होते हुए वापस अपने निर्धारित गंतव्य पर पहुंचेगी।

रैली में नर्सिंग छात्र-छात्राएं शामिल होकर आम नागरिकों को नेत्रदान के महत्व, इसकी आवश्यकता तथा मृत्यु के बाद नेत्रदान के माध्यम से किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने के संबंध में जागरूक करेंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिलेवासियों से नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा पखवाड़े के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने की अपील की है।

8 घंटे में चोरी का खुलासा, पेंट की जेब से उड़ाए 12 हजार, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 8 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घर से 12 हजार रुपये नगद चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला पंडरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मेन रोड मोवा स्थित एक किराना दुकान संचालक के घर का है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 19 अगस्त की रात परिवार के साथ सोने के बाद सुबह पत्नी घर का दरवाजा हल्का बंद कर दुकान खोलने चली गई थी। इसी दौरान घर में पेंट की जेब में रखे 12 हजार रुपये गायब हो गए। काफी तलाश के बाद भी रुपये नहीं मिलने पर थाना पंडरी में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू की। घटना स्थल और आसपास लगे सीटीवी कैमरों की जांच की गई। फुटेज में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घर वाली गली में आता-जाता दिखाई दिया। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध की पहचान पंकज सोनवानी के रूप में की। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने घर का दरवाजा हल्का खुला देखकर अंदर प्रवेश कर 12 हजार रुपये चोरी करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी ने बताया कि चोरी की रकम में से 5 हजार रुपये खर्च कर दिए गए हैं, जबकि 7 हजार रुपये उसके पास मौजूद हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 हजार रुपये नगद बरामद कर विधिवत जब्त कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंकज सोनवानी पिता स्व. मोहन सोनवानी, उम्र 27 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती सतनामी पारा, मोवा थाना पंडरी रायपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पंडरी थाना पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है।

सम्पादकीय

बदलते भारत ने बदला अमेरिका का नजरिया

कश्मीर को लेकर अब दुनिया का नजरिया बदलने लगा है। इसे समझने के लिए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का जम्मू-कश्मीर दौरा अहम है। आर्टिकल-370 हटने के बाद किसी अमेरिकी राजदूत का कश्मीर में पहला आधिकारिक दौरा और इस दौरान जम्मू-कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा बताना महज एक औपचारिक बयान नहीं है, बल्कि यह उस बदलते भारत की तस्वीर है जो अब आंखों में आंखें डालकर बात करता है और दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका पाक समर्थित बयान देता आया है और शुरुआती दशकों में अमेरिका जम्मू-कश्मीर को एक 'विवादित क्षेत्र' और भारत-पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय राजनीतिक समस्या के रूप में देखता रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी राजदूत ने कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की भी तारीफ की। उन्होंने माना कि नई दिल्ली और स्थानीय सरकार ने सुरक्षा के लिए काफी काम किया है। अमेरिका अपने नागरिकों के लिए जारी ट्रैवल एडवाइजरी में इस स्थिति को ध्यान में रखेगा, यह संकेत भी अपने आप में अहम है। कश्मीर की कहानी लंबे समय तक आतंकवाद, अलगाववाद, हिंसा और अशांति के इर्द-गिर्द घूमती रही है। 1989 के बाद घाटी में शुरू हुई हिंसा ने न केवल स्थानीय जीवन को प्रभावित किया, बल्कि दुनिया के सामने कश्मीर की एक ऐसी छवि बनाई, जिसमें सामान्य जिंदगी और विकास पीछे छूट गए। विदेशी सरकारों ने भी अपने नागरिकों को यहां यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिका की लेवल-4 ट्रैवल एडवाइजरी इसी लंबे सुरक्षा संकट की अंतरराष्ट्रीय अभिव्यक्ति रही है। पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदलने की कोशिश स्पष्ट दिखाई देती है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ पर्यटन, निवेश, आधारभूत ढांचे और लोकतांत्रिक गतिविधियों पर जोर बढ़ा है। ऐसे में किसी बड़े देश के राजदूत का कश्मीर पहुंचकर स्थिति का प्रत्यक्ष आकलन करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह दौरा भारत की कूटनीतिक सफलता के लिहाज से भी अहम है। भारत लगातार यह कहता रहा है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न हिस्सा है और यहां की स्थिति को बाहरी नजरिए से नहीं, बल्कि जमीनी वास्तविकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का यह कहना कि बातचीत में जम्मू-कश्मीर से जुड़े पुराने मुद्दों पर भी चर्चा हुई, बताता है कि कश्मीर की कहानी केवल केंद्र और विदेशी सरकारों के बीच कूटनीतिक संवाद तक सीमित नहीं है। स्थानीय सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। यदि सुरक्षा के साथ राजनीतिक संवाद और विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो बदलाव अधिक टिकाऊ होगा। अब अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव इस बदलती तस्वीर की अगली बड़ी परीक्षा हो सकती है। यदि भविष्य में अमेरिका अपने नागरिकों के लिए कश्मीर को लेकर चेतावनी का स्तर कम करता है, तो इससे पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय धारणा दोनों को सकारात्मक बल मिलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सुरक्षा और सामान्य स्थिति को लगातार बनाए रखा जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बदलते भारत ने दुनिया को नजरिया बदलने का कारण दिया है और गोर का दौरा इसका महत्वपूर्ण संकेत है। भारत के लिए अब चुनौती केवल यह साबित करना नहीं है कि कश्मीर बदल गया है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि यह बदलाव स्थायी, समावेशी और दिखाई देने वाला हो, तभी बदलते भारत की तस्वीर दुनिया की नजरों में पूरी तरह मजबूत होगी।

रक्षा क्षेत्र में बदलती भारत की तस्वीर

आत्मनिर्भरता

महेन्द्र तिवारी

रक्षा उत्पादन विभाग ने 18 अगस्त 2026 को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 405 वस्तुओं वाली छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है। इन वस्तुओं का अनुमानित कारोबार मूल्य 3,070 करोड़ रुपये है। इसका लक्ष्य ऐसा मजबूत राष्ट्रीय रक्षा औद्योगिक तंत्र तैयार करना होना चाहिए जो सेना की जरूरतों को समय पर पूरा करे, नई तकनीक विकसित करे, युवाओं को रोजगार दे, उद्योगों को अवसर प्रदान करे और भारत को विश्व के रक्षा बाजार में एक विश्वसनीय निर्माता के रूप में स्थापित करे। यदि नीति, उद्योग, अनुसंधान और सैन्य जरूरतों के बीच प्रभावी तालमेल बना रहा तो आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा।

भारत की रक्षा नीति इन दिनों एक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, जिसमें लक्ष्य केवल विदेशी हथियारों और सैन्य उपकरणों की खरीद करना नहीं, बल्कि उनके निर्माण की पूरी व्यवस्था को देश के भीतर विकसित करना है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने 18 अगस्त 2026 को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण 405 वस्तुओं वाली छठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है। इन वस्तुओं का अनुमानित कारोबार मूल्य 3,070 करोड़ रुपये है। सूची में भारतीय तटरक्षक बल से संबंधित 16 वस्तुएं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित 389 वस्तुएं शामिल हैं।

यह निर्णय भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पहली दृष्टि में 405 वस्तुओं की संख्या सामान्य लग सकती है, लेकिन इस सूची का वास्तविक महत्व इसकी संख्या से कहीं अधिक है। इसमें केवल बड़े हथियार या सैन्य वाहन शामिल नहीं हैं, बल्कि उनके लिए आवश्यक उपप्रणालियां, कलपुर्जे, अतिरिक्त पुर्जे, उपसंयोजन और कच्चा माल भी शामिल हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत अब रक्षा आत्मनिर्भरता को केवल लड़ाकू विमान, टैंक, हेलीकॉप्टर या युद्धपोत बनाने तक सीमित नहीं रखना चाहता। उसकी कोशिश उन छोटी से छोटी वस्तुओं को भी देश में बनाने की है, जिनकी उपलब्धता किसी बड़े सैन्य उपकरण के संचालन के लिए अनिवार्य होती है। नई सूची में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 मार्क-I, हल्के लड़ाकू विमान और एएल 31 एफपी इंजन जैसे वायु मंचों से जुड़ी वस्तुएं शामिल हैं। इसके अलावा टी-72, टी-90 और बीएमपी-2 जैसे बख्तरबंद सैन्य मंचों से संबंधित सामग्री भी सूची में है। युद्धपोतों, मिसाइल प्रणालियों, रडार, सोनार, अग्नि नियंत्रण प्रणाली और उपग्रह संचार जैसी महत्वपूर्ण रक्षा प्रणालियों से जुड़ी वस्तुओं को भी स्वदेशीकरण के दायरे में लाया गया है। उच्च विस्फोटक टैंक रोधी गोला बारूद तथा अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण भी इसका हिस्सा हैं। इस निर्णय को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि आधुनिक युद्ध केवल बड़े हथियारों से नहीं लड़ा जाता। किसी लड़ाकू विमान की क्षमता उसके इंजन के साथ साथ उसके रडार, संचार उपकरण, नियंत्रण प्रणाली और अनेक छोटे कलपुर्जों पर निर्भर करती है। इसी तरह टैंक केवल उसके मुख्य हथियार से प्रभावी नहीं होता, बल्कि उसकी दृष्टि प्रणाली, संचार व्यवस्था, इंजन, सुरक्षा उपकरण और अनेक अन्य प्रणालियां उसके युद्धक प्रदर्शन को निर्धारित करती हैं। यदि इन महत्वपूर्ण हिस्सों में से किसी एक की आपूर्ति विदेश से रुक जाए तो पूरा सैन्य मंच प्रभावित हो सकता है। इसलिए वास्तविक रक्षा आत्मनिर्भरता का अर्थ हथियारों के साथ उनकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। यही कारण है कि नई सूची भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। युद्ध जैसी आपात स्थिति में किसी देश की सैन्य शक्ति केवल उसके पास मौजूद हथियारों की संख्या से तय नहीं होती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह अपने हथियारों को कितने लंबे समय तक सक्रिय रख सकता है। यदि किसी महत्वपूर्ण पुर्जे के लिए विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता बनी रहे तो युद्ध की स्थिति में सैन्य तैयारी प्रभावित हो सकती है। स्वदेशी

उत्पादन ऐसी निर्भरता को कम करता है और सेना को आवश्यक सामग्री की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय उद्योग के लिए खुलने वाला नया बाजार है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नई सूची में शामिल प्रत्येक वस्तु के स्वदेशीकरण के लिए एक सांकेतिक समयसीमा तय की गई है। स्वदेशी विकास सफल होने के बाद इन वस्तुओं की खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और भारतीय तटरक्षक बल उद्योग की भागीदारी के साथ विभिन्न माध्यमों से इन वस्तुओं के स्वदेशीकरण का कार्य करेंगे। इसमें छोटे और मध्यम उद्योगों की भागीदारी को महत्व दिया गया है। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना लंबे समय तक कठिन माना जाता रहा है। रक्षा उपकरणों की जटिल तकनीक, कठोर गुणवत्ता मानक और सीमित बाजार के कारण छोटी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में निवेश करना जोखिमपूर्ण रहा है। यदि सरकार और रक्षा सार्वजनिक उपक्रम पहले से यह स्पष्ट कर दें कि किन वस्तुओं की खरीद देश के भीतर से की जाएगी, तो उद्योगों को उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए अधिक निश्चितता मिलती है। इससे निजी निवेश बढ़ सकता है और नई तकनीक विकसित करने की प्रक्रिया को गति मिल सकती है। इस दिशा में सृजन रक्षा पोर्टल की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों और सेवा मुख्यालयों द्वारा आवश्यक रक्षा सामग्री को देश के उद्योगों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों तथा नवोदित कंपनियों के सामने रखना है, ताकि उनका स्वदेशी विकास और उत्पादन किया जा सके। जून 2026 तक इस पोर्टल के माध्यम से 33,000 से अधिक रक्षा वस्तुओं को स्वदेशीकरण के लिए उद्योगों के सामने उपलब्ध कराया जा चुका था। हालांकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह चुनौतियों से मुक्त नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती गुणवत्ता की है। सामान्य औद्योगिक उत्पाद और सैन्य उपकरण एक समान नहीं होते। रक्षा क्षेत्र में किसी छोटे पुर्जे की खराबी भी गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। इसलिए भारतीय कंपनियों को केवल कम लागत में वस्तु बनाने की क्षमता विकसित करने के बजाय उच्च विश्वसनीयता और कठोर परिस्थितियों में लगातार काम करने की क्षमता विकसित करनी होगी। दूसरी चुनौती अनुसंधान और विकास की है। यदि भारत केवल विदेशों में विकसित तकनीक की नकल करके पुर्जे बनाने तक सीमित रहता है तो इसे वास्तविक आत्मनिर्भरता नहीं कहा जा सकता। असली आत्मनिर्भरता तब होगी जब भारतीय वैज्ञानिक, अभियंता, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और उद्योग मिलकर नई तकनीक विकसित करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भविष्य की प्रतिस्पर्धा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मानवरहित प्रणालियों, उन्नत सामग्री, अंतरिक्ष तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और अत्याधुनिक सेंसर जैसी तकनीकों पर अधिक निर्भर होगी,इसलिए स्वदेशीकरण को अनुसंधान से जोड़ना आवश्यक है। रक्षा आत्मनिर्भरता का अंतिम लक्ष्य आयात के आंकड़े घटाना भर नहीं होना चाहिए। इसका लक्ष्य ऐसा मजबूत राष्ट्रीय रक्षा औद्योगिक तंत्र तैयार करना होना चाहिए जो सेना की जरूरतों को समय पर पूरा करे, नई तकनीक विकसित करे, युवाओं को रोजगार दे, उद्योगों को अवसर प्रदान करे और भारत को विश्व के रक्षा बाजार में एक विश्वसनीय निर्माता के रूप में स्थापित करे। यदि नीति, उद्योग, अनुसंधान और सैन्य जरूरतों के बीच प्रभावी तालमेल बना रहा तो आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। यह भारत के औद्योगिक विकास, तकनीकी क्षमता, रोजगार और सामरिक स्वायत्तता को भी नई गति दे सकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मुद्दा

डॉ. मोनिका शर्मा

निलंबित करना काफी नहीं

सख्त सजा से रुकेगी रैगिंग

बीते दिनों सूरत मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष के छात्र ने वरिष्ठ छात्रों द्वारा की जा रही रैगिंग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। प्रथम वर्ष के नौ रेजिडेंट डॉक्टरों और आत्महत्या करने वाले छात्र के पिता की शिकायत के आधार पर हुई कार्रवाई के तहत चार रेजिडेंट डॉक्टरों को अनुशासनहीनता और गंभीर लापरवाही के कारण छह महीने के लिए निलंबित किया गया है। छात्रों द्वारा लिखित शिकायत में चारों रेजिडेंट डॉक्टरों पर मानसिक उत्पीड़न, गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाने के बाद कॉलेज की एंटी-रैगिंग कमेटी ने यह कार्रवाई की है। सवाल यह है कि किसी परिवार के सपने उजाड़ने और एक युवक को जिंदगी से हारने की मनः स्थिति तक लाने वालों के लिए यह सजा काफी है? क्या गिनती के महीनों के लिए निलंबन भर की सजा से विद्यार्थियों का मनोबल तोड़ने वाली पीड़ादायी घटनाओं की पुनरावृत्ति रुकेगी? अपने जूनियर छात्रों को अपमानित करने की बर्बर सोच और संवेदना शून्य व्यवहार वाले डॉक्टरों पर दंड का क्या ही असर होगा? सच तो यह है कि नाममात्र सजा मिलना ही इन घटनाओं के दोहराव का कारण है। विडम्बना ही है कि नए सत्र में परिचय और वरिष्ठता की हनक दिखाने के नाम पर रैगिंग की भयावह परम्परा हर साल कई विद्यार्थियों का जीवन लील जाती है। पहली बार घर से दूर गए बच्चों के लिए मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का कारण बनती है। स्कूलों से लेकर व्यावसायिक कॉलेजों तक, रैगिंग की बेहूदा घटनाओं आते रहते हैं। जबकि ऐसे वाकये भावी प्रतिभाओं को ही नहीं पूरे परिवार और समाज को आघात पहुंचाने वाले हैं। आखिर क्यों देश के हर हिस्से में स्कूल-कॉलेज आए नये बच्चे भय और चिंता झेलने को विवश हों? देखा जाए तो ऐसे किसी दस्तूर की जरूरत ही क्या है? भविष्य बनाने के नये पड़ाव पर संस्थान के अपरिचित परिवेश में पहले ही भय से जूझ रहे का मनोबल तोड़ना कहां तक उचित है?

इन स्थितियों का नये बच्चों को संबल देने, सहज रहने के बजाय संस्थान का माहौल बिगाड़ने में ज्यादा योगदान है। बच्चों को पढ़ाई-लिखाई से ही विमुख करने वाली यह बर्बरता बहुत से बच्चों को आत्महत्या करने की कगार पर ले जाती है। बहुत से बच्चे तो भय के परिवेश में पढ़ाई तक छोड़ देते हैं। वस्तुतः, शारीरिक पीड़ा पहुंचाने वाला यह दुर्व्यवहार बच्चों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी गहराई से प्रभावित करता है। कहना गलता नहीं होगा कि शोषण की मानसिकता लिए यह बर्ताव पीड़ित बच्चों के मानवाधिकारों का हनन ही है। बावजूद इसके कनिष्ठ विद्यार्थियों को निर्वस्त्र करना, यौन उत्पीड़न, घृणित स्तर का मजाक, अपशब्द कहना और जबरन नशा करवाना तक अब रैगिंग का हिस्सा बन गए हैं। जीवन तक छीन लेने वाले इस बर्बर बर्ताव में सीनियर छात्र अपनी हनक दिखने के नाम पर निम्नतम स्तर की विकृत मानसिकता का परिचय देने लगे हैं। बावजूद इसके कारवाई के नाम पर सस्पेंड भर करने की खाना पूर्ति इनका दुस्साहस बढ़ाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 से ही रैगिंग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी कई नियम लागू किए गए हैं। यूजीसी द्वारा कॉलेजों में रैगिंग रोकने के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा चुका है कि प्रॉस्पेक्टस पर रैगिंग रोकने के नियमों और उससे जुड़े कानूनों को भी प्रकाशित करवाएं। कुछ साल पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी स्कूलों में रैगिंग के बढ़ते मामलों और खतरों को देखते हुए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए थे। ध्यातव्य है कि यूजीसी एंटी-रैगिंग रेगुलेशन-2009 देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू होता है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, केरल जैसे राज्यों ने अलग से कानून बनाया हुआ है। बावजूद इसके शिकायतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। नेशनल एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को देखें तो 2021 के मुकाबले 2025 में रैगिंग से संबन्धित शिकायतें दोगुनी हो गई हैं। संसद में पेश किए गए शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार साल 2022 से लेकर 2025 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं 51.64 प्रतिशत बढ़ी हैं। यह हाल तब है जब बहुत से विद्यार्थी भय के कारण शिकायत करने का साहस भी नहीं जुटा पाते। असल में नियम-क़ानूनों के बावजूद सख्त सजा न मिलने के कारण ही ऐसी बर्बर घटनाओं का होना जारी है। ऐसे मामलों में लिप्त लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी आवश्यक है। रैगिंग की हर घटना में ही दूसरों का भविष्य बिगाड़ती अमानवीय सोच रखने वालों के अपने भविष्य से जुड़ी सहज स्थितियां हर हाल में कायम रहती हैं। यही बात इस दुर्व्यवहार से जुड़े दुस्साहस को बढ़ाती है।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लोकहित में त्याग करने वाले ही बनते हैं संत

संकलित

दर्शन

सब कुछ क्षणिक होते हुए भी इस जगत की अनंत यात्र का कभी अंत नहीं होता। यह अनवरत गतिमान रहती है। वास्तव में त्याग की पवित्र भावना ही इसकी गतिशीलता और जीवंतता का कारण है। इसलिए जिन गुणों से मानव जीवन महान बनता है, त्याग उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे-शीतलता के बिना जल, दाहकता के बिना अग्नि, स्पर्श के बिना वायु का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार त्याग के बिना मानव जीवन का कोई मूल्य नहीं, परंतु त्याग वही सार्थक है, जो परार्थ के लिए हो। स्वार्थ के लिए त्याग तो पशु-पक्षी भी करते हैं। इसीलिए निःस्वार्थ भाव से लोकहित में त्याग करने वाले मानव संत बन जाते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता में त्याग को शांति का प्रदाता कहा गया है, परंतु इसके विलक्षण आनंद का अनुभव कोई विरला ही कर सकता है। वस्तुतः त्याग का जन्म उदारता से होता है, क्योंकि औदार्य भाव ही मनुष्य को स्वार्थ और मोह से मुक्तकर परार्थ के लिए प्रेरित करता है। इसलिए उदारता का भाव जिसमें जितना प्रबल होगा, त्याग की भावना भी उतनी ही प्रबल होगी। कल्पना कीजिए कि महर्षि दधीचि में उदारता का भाव कितना प्रबल रहा होगा, जिससे उन्होंने जीवित रहते ही लोक कल्याणार्थ शरीर त्याग करने का निर्णय लिया। कर्ण ने यह जानते हुए भी कि जीवन रक्षक कवच का दान करने से उसके प्राणों पर संकट निश्चित है, उसे सहर्ष काटकर याचक को समर्पित कर दिया। उदारता के बिना यह कदापि संभव नहीं था।

मनोबल जगाने की जरूरत

संकलित

प्रेरणा

राजा सुकीर्ति के पास एक लौहश्रुन्घ नामक हाथी था। राजा ने कई युद्ध में उस पर चढ़ाई करके विजय पायी थी। बचपन से ही उसे इस प्रकार से तैयार किया गया था कि युद्ध में शत्रु सैनिको को देखकर वो उनपर इस तरह टूट पड़ता। समय गुजरता गया, अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था। इसलिए अब राजा उसे युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। वह सिर्फ हाथी शाला की शोभा बन कर रह गया। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धँस गया और फिर धँसता ही चला गया। हाथी के फँसने का समाचार राजा तक भी पहुँचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास ईकट्ठे हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे। लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध मार्गभ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रीमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गये और अनुरोध किया। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया। और फिर राजा को सुझाव दिया कि युद्ध का माहौल बनाया गया, वाद्ययंत्र मंगवाए गए। नगाड़े बजवाये गए और ऐसा माहौल बनाया गया कि शत्रु सैनिक लौहश्रुन्घ की ओर बढ़ रहे है। और फिर तो लौहश्रुन्घ में एक जोश आ गया। गले तक कीचड़ में धंस जाने के बावजूद वह जोर से चिंघाड़ लगाकर सैनिकों की ओर दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे संभाला गया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर उत्साह के संचार करने की थी।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय मुसलमानों की भूमिका

सैय्यद जाहिद अली रियासत

भारत की स्वतंत्रता का इतिहास विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों से संबंधित करोड़ों भारतीयों के सामूहिक संघर्ष और बलिदानों की कहानी है। इस राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय मुसलमानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हर मोर्चे पर योगदान दिया। कुछ ने रणभूमि में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुछ ने पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया, जबकि अनेक धार्मिक विद्वानों ने जनचेतना जगाई और राजनीतिक नेताओं ने स्वतंत्र भारत की प्राप्ति की दिशा में आंदोलन का मार्गदर्शन किया। बहादुर शाह जफर, मौलवी मुहम्मद बाकर, मौलाना फजल-ए-हक खैराबादी, सर सैयद अहमद खान, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसी प्रमुख हस्तियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, आज भी बहुत नहीं गर्व से याद किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का योगदान न तो किसी एक क्षेत्र तक सीमित था और न ही किसी एक गतिविधि के क्षेत्र तक। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश विस्तारवाद के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध प्रस्तुत किया, बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह के दौरान प्रतीकात्मक नेतृत्व प्रदान किया; मौलवी मुहम्मद बाकर ने पत्रकारिता को प्रतिरोध का एक शक्तिशाली माध्यम बनाया; मौलाना फजल-ए-हक खैराबादी ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया; सर सैयद अहमद खान ने शैक्षिक और सामाजिक सुधारों की नींव रखी; मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने संयुक्त राष्ट्रवाद की अवधारणा का समर्थन किया; हसरत मोहानी भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले शुरूआती नेताओं में शामिल थे; और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने राजनीतिक नेतृत्व, पत्रकारिता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों ने विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता के रूप में स्वीकार किया। यद्यपि उनकी राजनीतिक सत्ता सीमित थी, फिर भी उनके नेतृत्व ने विभिन्न क्षेत्रों के स्वतंत्रता सेनानियों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट किया। विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून (वर्तमान का म्यांमार) निर्वासित कर दिया, जहाँ 1862 में उनका स्वर्गवास हुआ। उनकी कविताएँ देशभक्ति, निर्वासन और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरी लालसा की कालजयी अभिव्यक्ति बनी हुई हैं। मौलवी मुहम्मद बाकर को उर्दू पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। प्रसिद्ध दिल्ली उर्दू अखबार के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की कड़ी आलोचना की और 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता के उद्देश्य का खुलकर समर्थन किया। अपने अडिग रुख के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 16 सितंबर 1857 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें व्यापक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पहले शहीद पत्रकार के रूप में माना जाता है। मौलाना फजल-ए-हक खैराबादी एक प्रतिष्ठित इस्लामी विद्वान, दार्शनिक और साहित्यकार थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध का आह्वान करते हुए एक धार्मिक फतवा जारी किया। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक और धार्मिक समर्थन प्राप्त हुआ। विद्रोह के दमन के बाद उन्हें गिरफ्तार कर अंडमान द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अंततः वहीं उनका निधन हुआ। 1857 की घटनाओं के बाद सर सैयद अहमद खान ने भारतीय मुसलमानों के शैक्षिक और सामाजिक उत्थान के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की और मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। यद्यपि उन्होंने स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष में सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन उनके शैक्षिक सुधारों ने ऐसे प्रबुद्ध नेताओं की एक पीढ़ी तैयार की, जिन्होंने आगे चलकर भारत के राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैयद फजल-उल-हसन, जो हसरत मोहानी के नाम से प्रसिद्ध थे, एक प्रसिद्ध उर्दू कवि, पत्रकार और क्रांतिकारी नेता थे। वे भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले शुरूआती नेताओं में से एक थे। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कारावास का सामना किया और अपने लेखन, भाषणों तथा पत्रकारिता के माध्यम से देश को प्रेरित करते रहे। क्रांतिकारी नारा ह्लइंकलाब ज़िंदाबादह्व (क्रांति अमर रहे) व्यापक रूप से उनसे जोड़ा जाता है और बाद में यह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारों में से एक बन गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। अपने समाचारपत्रों अल-हिलाल और अल-बलाग के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की आलोचना की और जनता में राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1940 से 1946 के बीच स्वतंत्रता आंदोलन में निर्णायक नेतृत्व की भूमिका निभाई। वे हिंदू-मुस्लिम एकता के दृढ़ समर्थक थे और उन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया। स्वतंत्रता के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और आधुनिक शैक्षणिक संस्थानों, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक संगठनों के विकास में उनका योगदान स्थायी महत्व रखता है। ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति, समुदाय या राजनीतिक संगठन की उपलब्धि नहीं थी। बल्कि यह भारतीय समाज के हर वर्ग के लोगों के सामूहिक बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम थी। ऊपर उल्लिखित प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों के अलावा हजारों मुस्लिम विद्वानों, स्वतंत्रता सेनानियों, पत्रकारों, कवियों, लेखकों, राजनीतिक नेताओं और आम नागरिकों ने स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए अपार बलिदान दिए। अनेक लोगों ने औपनिवेशिक अधिकारियों के हाथों कारावास, निर्वासन और मृत्युदंड तक सहन किया। भारतीय मुसलमानों का योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक अनिवार्य और स्थायी अध्याय है। उनके बलिदान इस बात की स्थायी याद दिलाते हैं कि भारत की स्वतंत्रता एकता, साझा प्रतिबद्धता और देश के सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राप्त हुई। उनकी विरासत आज भी देशभक्ति, साहस, राष्ट्रीय एकता और जनसेवा के मूल्यों के साथ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। भारत के स्वतंत्रतासंग्राम में मुसलमानों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता नाही उसे हाशिए पर किया जा सकता है,

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है

ट्रेंड

पदों की संख्या कम

हम आईएएस, आईएफएस और आईपीएस पदों की संख्या कम कर रहे हैं। योजनाओं को ठीक से लागू करने के लिए जितने की जरूरत होगी, उतने ही रखे जाएँगे। इससे राज्य के लगभग 200 करोड़ रुपये बचेंगे।
-**सुखविंदर सिंह सुखु**, सीएम, हिमाचल प्रदेश

रिपोर्ट पर कार्रवाई

हमने सदन में कैग की 19 रिपोर्ट पेश की, जिनमें से हर एक में केजरीवाल सरकार के समय हुए किसी न किसी घोटाले का जिक्र था। इन सभी रिपोर्ट पर कार्रवाई चल रही है। सत्येंद्र जैन ने जल बोर्ड में घोटाला किया था, इसी वजह से वे जेल गए है। कार्रवाई जारी है और एजेंसियां अपना काम कर रही है।
- **रेखा गुप्ता**, सीएम, नई दिल्ली

अमित शाह का दबाव

गिरफ्तारी तब की जाती है जब पुलिस को किसी व्यक्ति से पूछताछ करनी हो। पुलिस ने सत्येंद्र जैन को हिरासत में नहीं लिया। इसका मतलब है कि सत्येंद्र से पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ़अमित शाह के दबाव में गिरफ्तार किया गया है।
-**अरविंद केजरीवाल**, पूर्व सीएम, नई दिल्ली

ऊर्जा का स्रोत

गुस्सा भले ही ऊर्जा का स्रोत लगे, लेकिन यह अंधा होता है। इसके कारण हम अपना संयम खो बैठते हैं। नकारात्मक भावनाएं, जो अक्सर अचानक उठने वाली इच्छा से पैदा होती हैं, उन्हें तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता।
- **दलाई लामा**, आध्यात्मिक गुरु

आरएसएस पर राहुल गांधी का हमला

एक समूह कैसे जान सकता है 1.5 अरब लोगों की सच्चाई, यह गलत

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली में 'हरा भरा स्वराजः राजीव गांधी के विजन को श्रद्धांजलि' कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने

आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या कोई समूह यह तय कर सकता है कि देश के हर व्यक्ति की सच्चाई वही जानता है। राहुल गांधी ने कहा कि केवल 1.5 अरब लोग ही अपनी सच्चाई जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वह यह मान लें कि वह किसी दूसरे व्यक्ति की सच्चाई जानते हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति के अनुभवों और परिस्थितियों को नहीं देखा है।

> राहुल गांधी ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि वह भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धर्म, समुदाय, उम्र या महिला-पुरुष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए

हर कारोबार का मालिक एक ही व्यक्ति तो स्वराज संभव नहीं

राजनीतिक व्यवस्था की पहुंच गांवों और पंचायतों तक हो

सोनिया की किताब पर भावुक हुए राहुल

बोले- आपको और पापा को 35 साल पहले साथ देखा था

सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव' नवंबर में प्रकाशित होने जा रही है। इस मौके पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर अपनी मां के लिए लिखे संदेश में कहा कि मां, मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल से भी अधिक समय पहले साथ देखा था। जिस दिन से पापा हमें छोड़कर गए, उस दिन से मैंने आपको जिंदगी की ओर से सामने आई हर चुनौती का सामना अटूट साहस और गरिमा के साथ करते देखा है। सिर्फ प्रियंका और मैं ही वास्तव में जानते हैं कि आप किन परिस्थितियों से गुजरी हैं और पापा के बाद आपकी जिंदगी कितनी कठिन रही।

10 नवंबर को प्रकाशित होगी

अमेरिकी प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस की इम्प्रिंट अल्फ्रेड ए. नॉफ ने घोषणा की कि 'बिलॉन्गिंगः अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर को बाजार में आएगी। हालांकि, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भारत में किताब के प्रकाशन की तारीख की अभी पुष्टि नहीं की है। आत्मकथा में सोनिया गांधी के इटली के बचपन, राजीव गांधी से प्रेम और विवाह, गांधी परिवार में प्रवेश, इंदिरा और संजय गांधी की मौत, राजनीति में आने के कारणों और 2004 में प्रधानमंत्री पद ठुकराने जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग शामिल हैं।

पूर्व पीएम राजीव गांधी को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि

पूर्व पीएम राजीव गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने 'एक्स' पर लिखा कि भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम की जयंती के मौके पर वीर भूमि पहुंच सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने लिखा कि भारतीयों के बीच सद्भावना, हर दिल में करुणा और, हर नागरिक को न्याय और लोकतंत्र में समान अधिकार.. पापा, आपकी ये सीख मेरी शक्ति है और आपकी यादें मेरी हिम्मत।

स्वतंत्र रूप से रखें अपनी बात

राहुल ने कहा कि अगर देश के हर कारोबार का मालिक एक ही व्यक्ति हो तो बड़ी आबादी के लिए स्वराज संभव नहीं है। अगर एक व्यक्ति इस देश के हर एक कारोबार का मालिक है तो भारतीय लोगों की बड़ी आबादी के लिए स्वराज की कोई संभावना नहीं है। देश में कुछ लोगों के पास एयरपोर्ट, बंदरगाह और कंपनियां होनी चाहिए, जबकि दूसरे लोग ऐसे नौकरशाह होने चाहिए जो अपनी बात स्वतंत्र रूप से रख सकें और किसी कारोबारी के प्रभाव में आकर काम न करें।

महंगी शिक्षा पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने कहा कि गांधीजी का विजन कुछ बुनियादी व्यवस्थाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने महंगी शिक्षा व्यवस्था और असमान परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह विजन ऐसी वित्तीय व्यवस्था के साथ भी संभव नहीं है, जिस पर दो-तीन लोगों का एकाधिकार हो। राहुल गांधी ने राजनीतिक व्यवस्था की पहुंच गांवों और पंचायतों तक होने की जरूरत बताई।

हर व्यक्ति भारत का हिस्सा

राहुल गांधी ने कहा कि देश में हर व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि वह भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि धर्म, समुदाय, उम्र या महिला-पुरुष के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके मुताबिक हर एक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म, समुदाय, उम्र या लिंग का हो, यह महसूस होना चाहिए कि मैं यहां का हूं।

खबर संक्षेप

बीसीआई चेयरमैन के इस्तीफे की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर

वकीलों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से किए जा रहे इस प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन मिला है। प्रदर्शन के दौरान मनन मिश्रा पर वकीलों और कानून के छात्रों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के प्रमुख मुद्दों में वकीलों का कल्याण, अधिवक्ता अधिनियम, स्टाइपेंड, चैंबर और वकीलों की सुरक्षा शामिल है।

राम मंदिर निर्माण में नृपेंद्र मिश्रा के ही फैसलेः राय

अयोध्या। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने 9 पन्नों का एक बयान जारी

किया है। उन्होंने कहा कि नृपेंद्र मिश्रा ने राम मंदिर निर्माण से जुड़े कई अहम फैसले लिए और किसी अन्य के

फैसले को महत्व नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट बनाया उसमें 15 ट्रस्टी रखे गए। इसके अध्यश्र नृपेन्द्र मिश्रा बनाए गए। उन्हीं के सुझावों के आधार पर लार्सन एण्ड टूर्बो को मंदिर निर्माण के लिए चुना गया। भवनों के निर्माण के लिए नोएडा की फर्म डिजाईन एसोसिएट को नृपेन्द्र मिश्रा ने ही चुना।

कार के कुए में गिरने से 4 लोगों की मौत

हैदराबाद। तेलंगाना के सिद्दिपेट जिले में बुधवार देर शाम एक कार सड़क किनारे स्थित कुए में गिर

गई। हादसे में कार सवार दंपति और उनके दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०)

रा०प्र०क०/अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका पनमेश्वरी पति शिवराम, जाति चेरवा, निवासी ग्राम हसुली, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०म० द्वारा ग्राम हसुली स्थित भूमि खसरा नंबर 337, 336 रकबा कमशः 0.036, 0.047 हे. भूमि को विक्रेता झुरही पति अघनू, जाति कोरवा, निवासी ग्राम हसुली, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०म० द्वारा दिनांक 20.1.1996 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से कय किया गया है, विक्रेता झुरही की मृत्यु होने के कारण वर्तमान राजस्व अभिलेखों उनके उत्तराधिकारी सोमारू आ. विश्वनाथ वगैरह के नाम पर दर्ज है। आवेदिका द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण बावत आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16/09/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।आज दिनांक 17/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिकन तहसीलदार,
अम्बिकापुर-2

सुरक्षा देश की सबसे बड़ी जरूरत, अगर ये नहीं होती तो सीमा पर सेना भी नहीं होती

सेना देश की ईमानदार करदाता, हमारा वेतन सीधे टैक्स काटकर मिलता है

मामले ने पकड़ा तूल, लड़की ने मांगी दिल से माफी, बोली अब मुझे चैन आया

▶▶ नई दिल्ली

'हम जेन जी (जेन-Z) हैं, ये बकवास बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे टैक्स के पैसे से सेना को सैलरी मिलती है। आपने यह रोड ब्लॉक क्यों की हुई है? इसी तरह से आप कश्मीर के लोगों पर भी रोक लगाते हैं। हम यहां से नहीं हिलेंगे, आपको जो समझना है, वो समझो। अब तो ये बात संसद तक जाएगी, मैंने वीडियो बना लिया है, किसी को नहीं छोड़ूंगी'।

यह असभ्यता से भरे वो चंद अलफाज हैं, जिन्हें बीते दिनों लद्दाख के कारगिल स्थित मिनिमार्ग चेकपॉइंट पर एहतियातन कुछ देर के लिए सड़क बंद किए जाने से आगबबूला हुई एक युवा महिला पर्यटक ने वहां तैनात सेना, स्थानीय पुलिसकर्मियों व अन्य सुरक्षाबलों के लिए इस्तेमाल किया। घटना का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर अपलोड होने के ठीक एक दिन बाद गुरुवार को तेजी से वायरल हुआ। आम जनता समेत पूर्व सैन्यकर्मियों ने लड़की के व्यवहार पर सख्त नाराजगी जताई। जिसके बाद लड़की की अक्ल भी ठिकाने पर आ गई और उसने अपने इस व्यवहार के लिए भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा सभी सुरक्षाबलों के सामने खेद प्रकट करते हुए दिल से माफी मांग ली है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए लड़की के व्यवहार को 'जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है' वाली मानसिकता बताया है।

◆ कारगिल के मिनिमार्ग चेकपॉइंट पर महिला पर्यटक के बवाल पर नाराज सेना के पूर्व अधिकारियों की प्रतिक्रिया

देश की सुरक्षा सेना की जिम्मेदारी

मामले पर अपना पक्ष रखते हुए सेना के पूर्व अधिकारी (रिटायर्ड) मेजर जनरल एसबीएस अस्थाना ने कहा कि मिनिमार्ग में हंगामा करने वाली लड़की ने देश के एक गैर-जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार किया है। जो पूरी तरह से गलत है। आमतौर पर किसी भी जगह पर सेना का काम यातायात को नियंत्रित करने का नहीं होता है। लेकिन लद्दाख या कारगिल जैसे अति संवेदनशील इलाकों में सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की होती है। इसलिए वह ग्राउंड जीरो पर तैनात रहकर अपना दायित्व निभाती है। अगर देश की जरूरत नहीं होती तो सेना भी ऐसे इलाकों में तैनात नहीं होती। वर्तमान समय में बिना सुरक्षा के तो किसी देश की कल्पना नहीं की जा सकती है।

हक की मांग करने से पहले ये करें

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लन ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, हमारे सैनिक जिन क्षेत्रों में अपनी जान की बाजी लगाकर दिन-रात पहरेदारी करते हैं। आप उन जगहों पर छुट्टियां मनाने जा सकती हैं। लेकिन आपकी भाषा अच्छी परवरिश और स्कूली शिक्षा का प्रतिबिंब है। हमेशा सम्मानजनक रहें। हक की मांग करने से पहले एक अच्छे कानून का पालन करने वाले नागरिक बनना सीखें।

सैनिकों के बलिदान का अपमान

रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने लिखा, जहां यातायात को नियंत्रित किया जा रहा था। वहां पर यह टिप्पणी सैनिकों के बलिदान का अपमान है। सेना के कर्मी भी कर चुकाते हैं। सीमा क्षेत्र होने के कारण लद्दाख में सुरक्षा संवेदनशीलताएं हैं।

मेरा फ्यूचर खराब हो रहा है, माफी चाहती हूं

मामले के तूल पकड़ने और चौतरफा आलोचना से घिरने के बाद लड़की ने सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार के लिए माफी मांग ली है। एक निजी चैनल से बातचीत में कहा, मैं अपने जवान भाइयों, पूरी भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर की पुलिस और बाकी सुरक्षाबलों से दिल से माफी मांगती हूं। यह वो लोग हैं जो बॉर्डर पर हमारी सेवा करने के लिए तैनात रहते हैं। अगर सेना बॉर्डर पर नहीं होती तो हम अपने घरों में चैन की नींद नहीं सो रहे होते। मैं एक शांत और मदद करने वाली इंसान हूं। लेकिन उस दिन मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। वहां पर पीछे से मुझे भीड़ ने उकसाया, तभी मैंने यह सारी बातें फ्लो में अचानक बोल दी। जबकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जा रहा है, मेरे बारे में लोग बहुत गलत-गलत बातें कह रहे हैं, गंदे-गंदे कमेंट कर रहे हैं। मेरा परिवार काफी परेशान है, मेरा फ्यूचर भी खराब हो रहा है। जिसकी वजह से मैं आपके चैनल पर आई हूं। मैं अभी मेंटली और फिजिकली फिट नहीं हूं कि किसी और से बात कर सकूं। लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि बोलना जरूरी है। ताकि लोगों को ये न लगे कि मैं गलत हूं।

साइबर क्राइम रिपोर्ट करवाई

लड़की के मुताबिक, मैंने बिना अनुमति के मेरा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने को लेकर साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने इसकी एक कॉपी मुझे दी है। साथ ही कहा है कि जिसने भी आपकी अनुमति के बिना यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। वो गलत है। एक लड़की की प्राइवेसी और उसका फेस दिखाकर यह वीडियो अपलोड किया गया। जिससे मैं डिप्रेशन में चली गई हूं। मुझे इतना तनाव हुआ कि पैनिक अटैक ही आ गया। जिसके बाद साइबर क्राइम वालों को मेरे लिए एंबुलेंस बुलानी पड़ी।

यूं ईमानदार करदाता है सेना

उन्होंने बताया कि सेना के सभी कर्मी अपने वेतन से न केवल पूरा टैक्स देते हैं। बल्कि मैं उन्हें देश का सबसे ईमानदार टैक्सपेयर कहता हूं। क्योंकि हमारा वेतन सीधे टैक्स कटकर (सीडीए से टैक्स कटने की व्यवस्था) ही हमें मिलता है। कहीं पर भी कोई टैक्स चोरी नहीं होती है।

रोड ब्लॉक की असली वजह

मेजर जनरल अस्थाना ने कहा कि लद्दाख या केंद्रशासित प्रदेश की बाकी जगहों पर सेना खासतौर पर सुरक्षा कारणों की वजह से ही रोड ब्लॉक करती है। जिसमें कई बार संबंधित स्थान पर आतंकवादियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना, कभी पहाड़ खिसकने, उससे पत्थर गिरने या वीआईपी मूवमेंट जैसी चीजें भी इसकी वजह बनती हैं। उदाहरण के लिए आतंकी घुसपैठ के दौरान अगर रोड बंद नहीं की जाएगी और वहां से गुजरने वाले सभी लोगों, वाहनों की अच्छी तरह से पड़ताल नहीं की जाएगी। तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। कारगिल के इलाके में पहाड़ काफी ढीले हैं, जिनसे अक्सर पत्थर टूटकर गिरते हैं। इसकी जानकारी सेना को वहां की जाने वाली नियमित हवाई गश्त से मिलती है। ऐसे में अगर कुछ देर के लिए सड़क बंद नहीं की जाएगी। तो आम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अंत में अभी लेह में अमेरिका के राजदूत का दौरा चल रहा है या ऐसा कोई और वीवीआईपी मूवमेंट हो तो भी सुरक्षा के लिहाज से सेना, स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रोड ब्लॉक करती है। जिसमें कुछ भी गैरकानूनी या मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित नहीं है।

31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक

नदी जल विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर हुई चर्चा

बैठक में गृह मंत्री शाह व अन्य सीएम

एजेंसी ▶▶ चेन्नई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को मामल्लापुरम के पास कोवलम के होटल में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय ने अमित शाह के आगमन पर उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग को मजबूत करना, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल थे। प्रतिभागियों द्वारा महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष त्वरित अदालतों की स्थापना के प्रस्ताव की भी जांच की गई। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, केरल के सीएम वीडी सतीशन और तेलंगाना के उप सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क उपस्थित थे। पुडुचेरी के सीएम एन रंगासामी उपस्थित नहीं थे, जबकि उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, लक्षद्वीप के अधिकारी और भाग लेने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।

लिव-इन रिलेशनशिप पर हाईकोर्ट का फैसला

सहमति से वयस्कों का रिश्ता शादी के समान, कोई नहीं दे सकता दखल

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे वयस्कों का रिश्ता शादी के समान है। माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त उनकी पसंद में दखल नहीं दे सकते और न ही उनकी जान या स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकते हैं।

अदालत ने परिवार की ओर से धमकियों का सामना कर रहे एक लिव-इन कपल को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 13 अगस्त को दंपती की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और कानूनी रूप से एक-दूसरे से विवाहित नहीं हैं, लेकिन दोनों सहमति से वयस्क हैं, इसलिए उनका रिश्ता शादी के समान है।

दिल्ली हाईकोर्ट कॉम्पलेक्स

बदमाशों ने 14 फायर किए

कोर्ट से बरी होकर निकले गैंगस्टर विनोद की गोली मारकर की हत्या

एजेंसी ▶▶ हिसार

हरियाणा के हिसार कोर्ट में गुरुवार को पेशी पर आए गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काणा को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया गया। उसके दो साथियों को भी गोलियां मारी गईं। बाइक सवार दो बदमाशों ने ये वादात की, जिनमें एक को गैंगस्टर के साथियों ने पीछा कर दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक, विनोद पानू और उसके 12 साथी आज ही पांच साल पहले हुई हत्या के मामले में बरी हुए थे। कोर्ट का फैसला आने के बाद सभी बाहर निकले थे कि तभी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कुछ 14 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 10 पानू को लगना बताए जा है। इस वारदात के दो वीडियो भी सामने आए है। एक वीडियो में हमलावर गोली मारकर भागते हुए और फिर गैंगस्टर के साथी एक को पकड़ते हुए दिखाई दे रहे है।

फायरिंग करते हमलावार

सीबीएसई की तीन भाषा नीति में सुप्रीम कोर्ट की सलाह

'नेटिव' की जगह 'इंडिजिनस' का हो इस्तेमाल, यह एक स्वदेशी शब्द

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सीबीएसई की तीन-भाषा नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने नीति में इस्तेमाल किए गए 'नेटिव' यानी मूल भाषा शब्द पर सवाल उठाया।

जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने 'नेटिव' शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह औपनिवेशिक दौर से आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे इस सवाल पर भी विचार करना होगा कि भारत में अंग्रेजी को स्वदेशी या गैर-स्वदेशी भाषा माना जा सकता है या नहीं।

देखना होगा यह संविधान के अनुरूप है या नहीं

जस्टिस बागची ने कहा कि उन्हें 'नेटिव' शब्द के इस्तेमाल को लेकर आपत्ति है और इसकी जगह 'इंडिजिनस' यानी स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए था। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार करने वालों को 'नेटिव' शब्द के इस्तेमाल को लेकर सावधान होना चाहिए था। अदालत ने कहा कि इस सवाल को संवैधानिक दृष्टि से देखना होगा। यानी केवल भाषा के वर्गीकरण की बात नहीं है, बल्कि यह भी जांचना होगा कि इस तरह का वर्गीकरण संविधान के अनुरूप है या नहीं।

अवैध लिंग जांच में पुलिस नहीं दर्ज कर सकती एफआईआर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) कानून के तहत दर्ज अपराधों की जांच पुलिस नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में कार्रवाई कानून के तहत नामित अधिकारियों को ही करनी होगी। इस कानून से जुड़े मामले तकनीकी होते हैं।

विश्व छायाचित्र दिवस पर 35 छायाचित्रकारों का सम्मान

ठाणे : विश्व छायाचित्र दिवस के अवसर पर ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ और ठाणे महानगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में समाचारपत्र छायाचित्रकारों के छायाचित्रों की भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी का समापन समारोह और छायाचित्रकारों का सम्मान राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, विधायक संजय केळकर, महापौर शर्मिला पिंपळोलकर, उपमहापौर कृष्णा पाटील और पत्रकार संघ के अध्यक्ष दिलीप शिंदे की प्रमुख उपस्थिति में भव्य रूप से संपन्न हुआ। ठाणे शहर दैनिक पत्रकार संघ और ठाणे महानगरपालिका के संयुक्त तत्वावधान में 17 से 19 अगस्त तक ठाणे महानगरपालिका मुख्यालय में 150 छायाचित्रों की भव्य प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। ठाणे के 22 छायाचित्रकारों और 12 शौकिया छायाचित्रकारों के छायाचित्रों के माध्यम से ठाणे के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और विकास की तस्वीर को कैमरे में कैद किया गया था। इन छायाचित्रकारों का सम्मान कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागार में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, जिला सूचना अधिकारी मनोज सानप, जनसंपर्क अधिकारी प्राची डिंगणकर, जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष संजय पितळे, कै. यशवंतराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधि समिति के सदस्य कैलास म्हापदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के हाथों किया गया।

गुरुग्राम में आज होगा Gen-H स्टार्टअप समिट-युवा उद्यमी चौपाल का आयोजन

हरियाणा में युवा उद्यमिता को मिलेगी नई रफ्तार, 45 हजार आइडिया और 400 इंटरप्रेन्योर दिखाएंगे अपना हुनर

▶▶ नई दिल्ली

हरियाणा सरकार युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा मजबूत मंच तैयार कर रही है, जहां विचार, निवेश और सरकारी सहयोग एक साथ उपलब्ध होंगे। राज्य के आईडियाथॉन में अब तक 45,000 से अधिक आइडिया सामने आ चुके हैं। वहीं, करीब 400 युवा इंटरप्रेन्योर 21 अगस्त को Gen-H स्टार्टअप समिट-युवा उद्यमी चौपाल में अपने विचार और उद्यम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर गुरुग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, युवा उद्यमी, निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख लोग शामिल होंगे। हरियाणा सरकार के अनुसार इस आईडियाथॉन उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक रूप से नौकरी तलाशने के बजाय उद्यम खड़ा करने और रोजगार पैदा करने की दिशा में प्रेरित करना है। यह पहल केवल एक दिन के कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगी। इसका लक्ष्य ऐसा उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जहां युवा अपने शुरुआती विचारों को सफल व्यवसाय में बदल सकें और उन्हें मेंटरशिप, फंडिंग, अत्याधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा बाजार संबंधी व्यावहारिक मार्गदर्शन मिल सके।

400 युवा इंटरप्रेन्योर निवेशकों और उद्योग जगत से करेंगे संवाद

इस कार्यक्रम में करीब 400 युवा इंटरप्रेन्योर भाग लेंगे। इनमें से चुने गए 60 इंटरप्रेन्योर एक विशेष राउंडटेबल में हिस्सा लेंगे, जहां वे अपने विचारों, चुनौतियों और विकास की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में अपने दम पर सफल उद्यम खड़े करने वाले युवा उद्यमी अपनी संघर्ष और सफलता की कहानियां साझा करेंगे।

एआई और तकनीक से तैयार होंगे नए उद्यम

सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों पर विशेष जोर दिया जाएगा। युवाओं को बताया जाएगा कि एआई और नई तकनीकों का इस्तेमाल नए उत्पाद तैयार करने, कारोबार को बढ़ाने और वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए कैसे किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को हरियाणा में ही अपना उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां अच्छे विचारों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग मिल सके।

मुख्यमंत्री युवाओं से करेंगे सीधा संवाद

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ संवाद और इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र होगा। युवा उद्यमी और विद्यार्थी मुख्यमंत्री से उद्यमिता, नवाचार और हरियाणा के भविष्य से जुड़े सवाल सीधे पूछ सकेंगे। मुख्यमंत्री इनोवेशन वॉक के दौरान छात्र, इंटरप्रेन्योर द्वारा विकसित नए प्रोजेक्ट और स्टार्टअप भी देखेंगे। इसके अलावा चयनित उद्यमी स्टार्टअप फाउंडर्स राउंड टेबल में अपने अनुभव, चुनौतियां और नए विचार साझा करेंगे।

युवाओं को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय वर्ल्ड लीडर्स फोरम में वैश्विक आर्थिक जगत की प्रमुख हस्तियों के समक्ष छत्तीसगढ़ की तेजी से बदलती आर्थिक तस्वीर, निवेश की व्यापक संभावनाओं और भविष्य के विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब अपनी पारंपरिक औद्योगिक और खनिज आधारित पहचान से आगे बढ़कर युवा शक्ति, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक विनिर्माण पर आधारित नई अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल बड़े निवेश आकर्षित करना नहीं है, बल्कि निवेश को रोजगार, उद्यमिता, बेहतर आय और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ के युवा केवल रोजगार तलाशने वाले न रहें, बल्कि अपने नवाचार और उद्यमिता के बल पर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें, इसी सोच के साथ राज्य की नीतियों और योजनाओं को नया स्वरूप दिया जा रहा है। फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सहित भारत और विश्व की अनेक प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं।

6.31 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, 11.57 प्रतिशत की विकास दर

मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है और आर्थिक वृद्धि दर 11.57 प्रतिशत रही है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़कर 1 लाख 79 हजार 244 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए विकास और जनकल्याण को समान प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के 1.72 लाख करोड़ रुपये के बजट में अधोसंरचना निर्माण, पूंजीगत व्यय और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, रेल, ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत कर छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है।

नई औद्योगिक नीति के बाद 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30, वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों के माध्यम से निवेश प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध बनाया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में 450 से अधिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया है। इन सुधारों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है और नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद प्रदेश को 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब स्टील, सीमेंट और खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स, ग्रीन एनर्जी और फूड प्रोसेसिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों में निवेश के लिए नई संभावनाएं तैयार हुई हैं।

2030 तक 5 हजार स्टार्टअप, युवा बनेंगे रोजगार सृजक

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई अर्थव्यवस्था के केंद्र में युवा हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश के युवा केवल नौकरी की प्रतीक्षा करने वाले जॉब सीकर नहीं, बल्कि जॉब क्रिएटर बनें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2030 तक 5 हजार स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नए उद्यमियों को अपने अभिनव विचारों को व्यवसाय में बदलने के लिए 10 लाख रुपये तक सीड फंड सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के साथ युवाओं को तकनीक, नवाचार, कौशल और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने से न केवल नए व्यवसाय खड़े होंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी निर्मित होंगे। मुख्यमंत्री साय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छत्तीसगढ़ के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए कहा कि प्रदेश में 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके साथ ही नागरिकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सरकारी सेवाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि एआई का उद्देश्य केवल तकनीकी बदलाव नहीं है। इसका वास्तविक उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, युवाओं के लिए भविष्य के रोजगार और उद्यमिता के अवसर तैयार करना तथा सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन पर काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 100 एआई डेटा लैब और 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे तथा 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहयोग देने का लक्ष्य है। नवा रायपुर में करीब 1,000 करोड़ रुपये की लागत से एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जा रहा है।

आईजीकेवी में एंटोमोलॉजी पेपर लीक, परीक्षा रद्द, मंत्री के आदेश पर एफआईआर

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी विषय की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल जांच समिति गठित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मंत्री के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। साथ ही पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया है।

कैसे हुआ खुलासा?

विश्वविद्यालय में बीएससी द्वितीय वर्ष की एंटोमोलॉजी की परीक्षा सुबह 10:30 बजे होनी थी। परीक्षा से पहले सुबह 8:50 बजे कवर्धा से प्रश्नपत्र लीक होने की सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल परीक्षा निरस्त कर दी।

मंत्री के निर्देश पर कार्रवाई

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने मामले को गंभीरता से लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल जांच समिति गठित करने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए मंत्री के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई और पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है।

छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का नया प्रभात- समावेशी विकास और आधुनिकता से संवर रहा युवाओं का भविष्य

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राज्य में उच्च शिक्षा को अधिक सुलभ, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ऐतिहासिक और दूरगामी कदम उठाए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन तक, प्रदेश का उच्च शिक्षा क्षेत्र एक बड़े सकारात्मक बदलाव का साक्षी बन रहा है। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए सुदूर एवं ग्रामीण अंचलों में नए महाविद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ संचालित संस्थानों में नए संकायों और विषयों की शुरूआत की जा रही है। इसके अतिरिक्त, बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए सीटों में वृद्धि की स्वीकृति भी दी गई है।

अधोसंरचना और डिजिटल क्लासरूम का विस्तार

अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण के तहत भवनविहीन महाविद्यालयों के लिए नए भवनों का निर्माण, पुरानी इमारतों का संधारण और अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया जा रहा है। पठन-पाठन को तकनीक से जोड़ने के लिए कक्षाओं को स्मार्ट और ई-क्लासरूम में बदला जा रहा है, जहाँ

कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश के शासकीय, निजी एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्तर (बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी., बी.बी.ए., बी.सी.ए.) पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) लागू की जा चुकी है। पं. सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय (बिलासपुर) और इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय (खैरागढ़) में वर्ष 2025 से तथा सत्र 2025-26 से चार वर्षीय बी.एड, प्राच्य संस्कृत और बी.पी.एड में भी इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है।

वन मंत्री के निर्देश पर इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में वन्यजीव शिकार पर बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के निदेर्शानुसार छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों की सुरक्षा और अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए वन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में इन्द्रावती टाइगर रिजर्व, बीजापुर में वन विभाग की टीम ने वन्यजीव शिकार के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान वन्यप्राणी का मांस, संभावित रूप से नीलगाय का मांस, तथा शिकार में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री बरामद की गई।

मुखबिर की सूचना पर नीतिकाकलेर में कार्रवाई

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर परिक्षेत्र पासेवाड़ा के अंतर्गत ग्राम नीतिकाकलेर क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की। टीम ने 19 अगस्त को मौके पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से

सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।

बारिश के बीच भी वन अमले की लगातार गश्त

वन विभाग के अनुसार यह कार्रवाई अधिकारियों के मार्गदर्शन, मजबूत सूचना तंत्र और मैदानी अमले की सतत निगरानी का परिणाम है। मानसून के दौरान लगातार बारिश, नदी-नालों में बढ़े जलस्तर और कठिन आवागमन के बावजूद वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कर वन्यजीवों की सुरक्षा में जुटे हुए हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी

इन्द्रावती टाइगर रिजर्व में वन अपराध और अवैध शिकार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ ही वन अमले को लगातार सक्रिय रखा गया है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

मुख्यमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री से की नई दिल्ली में सौजन्य भेंट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर आत्मीय चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली प्रवास के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों को लेकर आत्मीय चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात के दौरान आपसी संवाद करते हुए राज्यों से जुड़े विकासात्मक मुद्दों और वर्तमान परिस्थितियों पर विचार-विमर्श किया। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। मुख्यमंत्री साय इन दिनों नई दिल्ली प्रवास पर हैं, जहां वे विभिन्न राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं।

श्रमिकों के सशक्तिकरण का नया दौर: छत्तीसगढ़ में श्रम कल्याण को मिल रही नई गति

सुरक्षित श्रम, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, सम्मानजनक रोजगार और डिजिटल सेवाओं का व्यापक विस्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। राष्ट्र निर्माण में श्रमिकों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा और समग्र विकास के बिना विकसित राज्य की कल्पना संभव नहीं है। इसी सोच को आधार बनाकर छत्तीसगढ़ शासन का श्रम विभाग श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के निर्देशन में श्रमिकों के हितों की रक्षा, सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता तथा आधुनिक तकनीक के माध्यम से सेवाओं को सरल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। राज्य सरकार के ढाई साल में श्रम विभाग की उपलब्धियाँ राज्य सरकार की श्रमिक हितैषी सोच और संवेदनशील प्रशासन का परिचायक हैं।

प्रशासनिक ढांचे का विस्तार, सेवाओं की बेहतर पहुंच

श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा श्रमिकों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने पाँच नए जिलों में श्रम पदाधिकारी कार्यालय स्थापित किए हैं। मंत्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पाँच श्रम पदाधिकारी कार्यालयों को सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के रूप में उन्नत किया गया है। अब प्रदेश में 10 सहायक श्रमायुक्त कार्यालय एवं 23 श्रम पदाधिकारी कार्यालय सहित कुल 33 श्रम कार्यालय संचालित हैं। इससे श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और योजनाओं के प्रभावी संचालन को नई गति मिली है।

औद्योगिक विकास और श्रमिक हितों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। छत्तीसगढ़ कारखाना नियम, 1962 में संशोधन कर निर्धारित सुरक्षा प्रावधानों के साथ महिलाओं के रोजगार के अवसरों का विस्तार किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 2021 में संशोधन के माध्यम से श्रम पहचान पंजीयन प्रमाण-पत्र अब 24 घंटे के भीतर जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे उद्योगों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सरल एवं पारदर्शी सेवाएँ उपलब्ध होंगी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा।

56 लाख से अधिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में

श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल तथा असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के माध्यम से अब तक लगभग 56.83 लाख संगठित, निर्माण एवं असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है। वर्ष 2026 में 30 जून तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लगभग 3.48 लाख श्रमिकों को बीमा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कौशल उन्नयन जैसी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया गया है। इन योजनाओं पर लगभग 173.32 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जो श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

निर्माण श्रमिकों को बढ़ी आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के अंतर्गत आवास निर्माण अथवा घर खरीदने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय निर्माण श्रमिकों के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

महिला श्रमिकों को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर

इसी प्रकार दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों एवं उनके समूहों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए सहायता राशि भी एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये कर दी गई है। इससे महिला श्रमिकों को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिल रहे हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहल

राज्य सरकार ने श्रमिक परिवारों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से अटल कैरियर निर्माण योजना प्रारंभ की है। इसके माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण

वहीं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। इस पहल से बीमारियों की प्रारंभिक पहचान, समय पर उपचार तथा स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।

उत्कृष्ट शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य की ओर

श्रमिक परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2026-27 से इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित बच्चों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। यह पहल श्रमिक परिवारों के बच्चों के भविष्य को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने का माध्यम बनेगी।

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के माध्यम से पंजीकृत निर्माण, संगठित एवं असंगठित श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 18 जिलों में 39 भोजन केन्द्र संचालित हैं, जो हजारों श्रमिकों के लिए राहत का माध्यम बने हुए हैं।

हाथी के हमले से गई मवेशी की जान, दर्जनों किसानों के खेत की फसल किया बर्बाद

दहशत में ग्रामीण, वन विभाग के खिलाफ पनप रहा आक्रोश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के प्रतापपुर क्षेत्र में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगल से निकलकर गांवों और खेतों की ओर पहुंच रहे हाथियों के कारण ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक ओर जहां हाथियों के हमले में हाल ही में एक ग्रामीण की जान जाने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं अब मवेशी भी हाथियों के निशाने पर आ गए हैं। बीती रात एक हाथी ने ग्रामीण के घर के समीप बंधे एक भैंसे को मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भय के साथ वन विभाग के प्रति नाराजगी भी बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार बीती देर रात हाथी ने पृथ्वी यादव की फसल और घर के पास बंधे मवेशियों को निशाना बनाया और एक भैंसे जान ले ली। वहीं खेतों में खड़ी फसलों को भी बुरी तरह रौंद दिया। ग्रामीणों के अनुसार मसगा के अशोक जायसवाल और सुदीप जायसवाल सहित दर्जनों किसानों के खेतों में हाथी पहुंचा और धान समेत अन्य फसलों को नुकसान पहुंचाया। बारिश के मौसम में किसानों द्वारा दिन-रात मेहनत कर तैयार की जा रही फसल को हाथियों द्वारा रौंदे जाने से ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान की चिंता सता रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथी पूरी रात गांव और खेतों के आसपास घूमता रहा। इस दौरान ग्रामीण अपने घरों में दुबके रहे। जिस हाथी को ग्रामीण आक्रामक बता रहे हैं, वह इंसानी आबादी के करीब पहुंच रहा है। पहले ग्रामीण की मौत और अब पालतू मवेशी की मौत की

घटना ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि हाथी को आबादी वाले क्षेत्र से दूर नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। इन दिनों खेतों में धान की फसल तैयार हो रही है। किसान बारिश के बीच दिन-रात खेतों में मेहनत कर फसल को बचाने में जुटे हैं। ऐसे समय हाथियों के खेतों में घुसने से किसानों की पूरी मेहनत कुछ ही घंटों में बर्बाद हो जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों के झुंड के अलावा अकेले घूम रहा आक्रामक हाथी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। हाथी कब और किस दिशा से गांव में पहुंच जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इससे ग्रामीणों को फसल के साथ-साथ अपने परिवार और मवेशियों की सुरक्षा की भी चिंता करनी पड़ रही है। लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का सवाल है कि यदि कोई हाथी लगातार आबादी के करीब पहुंचकर नुकसान कर रहा है और उसके आक्रामक व्यवहार की जानकारी सामने आ चुकी है, तो उसकी प्रभावी निगरानी और सुरक्षित प्रबंधन के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे। हाथी के आने के बाद निगरानी करने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। संवेदनशील गांवों में लगातार निगरानी दल तैनात करने, ग्रामीणों को समय पर सूचना देने और हाथी की गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि आक्रामक हाथी की तत्काल निगरानी कर उसे आबादी से दूर रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही प्रभावित किसानों की फसलों और मृत मवेशी का मौके पर आकलन कर नियमानुसार मुआवजा दिलाया जाए।

हाथियों की लगातार आवाजाही ने ग्रामीणों की सामान्य जिंदगी प्रभावित कर दी है। बरसात और अंधेरी रात में घरों से बाहर निकलना जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों को अपने परिवार, मवेशियों और खेतों की सुरक्षा के लिए रात में जागकर पहरा देना पड़ रहा है। एक तरफ हाथियों के हमले से मानव जीवन पर खतरा बना हुआ है, दूसरी तरफ मवेशियों की मौत और फसलों के नुकसान से आर्थिक संकट भी गहराने लगा है। लगातार हो रही घटनाओं ने प्रतापपुर क्षेत्र में वन्यजीव और मानव संघर्ष की गंभीर स्थिति को सामने ला दिया है।

जिले के 60 विवेचकों को एसपी ने वितरित किया हाईटेक स्मार्ट मोबाइल फोन

आधुनिक तकनीक से सशक्त होगी विवेचना, साक्ष्य संग्रहण को मिलेगा बढ़ावा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के निर्देशानुसार अपराधों की विवेचना को अधिक प्रभावी, तकनीक सक्षम एवं साक्ष्य-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल द्वारा जिले के 60 विवेचकों को हाईटेक स्मार्ट मोबाइल का वितरण किया है। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनता को समय पर न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक विवेचना गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध एवं कानून सम्मत हो इसी उद्धेश्य की पूर्ति के लिए यह हाईटेक स्मार्ट मोबाइल उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक विवेचक अपराध की विवेचना निष्पक्ष, वैज्ञानिक एवं समयबद्ध रूप से करते हुए नवीन आपराधिक कानूनों के प्रावधानों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक एवं

डिजिटल साक्ष्यों का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।

जिले के सभी विवेचक ई-साक्ष्य ऐप का शत प्रतिशत उपयोग करते हुए घटनास्थल का डिजिटल दस्तावेजीकरण, फोटो, वीडियो, लोकेशन एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित संकलन करें, जिससे विवेचना अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं न्यायालयीन प्रक्रिया के अनुसार हो। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हाईटेक स्मार्ट मोबाइल के माध्यम से विवेचक घटनास्थल का डिजिटल दस्तावेजीकरण, डिजिटल साक्ष्यों का सुरक्षित संकलन, वरिष्ठ अधिकारियों से त्वरित समन्वय तथा अनुसंधान संबंधी कार्यों का प्रभावी निष्पादन कर सकेंगे, जिससे अपराध अनुसंधान की गुणवत्ता एवं न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक मजबूती मिलेगी।

कलेक्टर ने वन, खनिज, उद्योग एवं श्रम विभाग के कार्यों की समीक्षा कर दिए प्रभावी कार्ययोजना के निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। शुक्रवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में वन, खनिज, उद्योग एवं श्रम विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं, राजस्व वृद्धि तथा

विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने सीएसआर मद से संचालित कार्यों तथा माइनिंग क्लोजर प्लान की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यों को प्राथमिकता और आवश्यकता के अनुरूप व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व वृद्धि के लिए प्रभावी कार्ययोजना के साथ कार्य करने पर जोर दिया।

श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले में श्रमिकों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वर्ष 2026-27 में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाने को कहा। साथ ही चॉइस सेंटर के माध्यम से श्रमिकों की शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कराने तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के समन्वय से ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक पंजीयन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वन विभाग की समीक्षा में कलेक्टर ने वन संरक्षण के साथ विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पौधरोपण एवं जल संरक्षण गतिविधियों की सतत निगरानी पर जोर दिया। उद्योग विभाग को स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्यमियों को आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने तथा लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

श्री श्याम निशान सेवा परिवार 23 को वितरित करेगा नि:शुल्क निशान एवं श्री श्याम चालीसा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। श्री श्याम निशान सेवा परिवार, सूरजपुर द्वारा श्री श्याम बाबा के 50वें वार्षिक उत्सव के पवन अवसर पर निःशुल्क निशान एवं श्री श्याम चालीसा का वितरण 23 अगस्त रविवार को प्रातः 10 बजे से रंगमंच स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण से किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य श्री श्याम बाबा के भक्तों में श्रद्धा एवं भक्ति की भावना को बढ़ावा देना तथा अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क निशान एवं श्री श्याम चालीसा उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम के अंतर्गत श्रद्धालुओं को निःशुल्क निशान सेवा प्रदान की जाएगी। आयोजकों द्वारा इस सेवा को किसी प्रदर्शन या अभियान के रूप में नहीं, बल्कि श्री श्याम बाबा के चरणों में अटूट श्रद्धा एवं सम्मान के भाव से आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजन में शुभम

अग्रवाल, संस्कार अग्रवाल, उपेन्द्र, आकाश, बालेंद्र साहू एवं उमेश सिंह सहित श्री श्याम निशान सेवा परिवार के सदस्य सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। आयोजकों ने श्याम प्रेमियों एवं श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर श्री श्याम बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने एवं निःशुल्क निशान व श्री श्याम चालीसा वितरण सेवा का लाभ लेने का आग्रह किया है।

महुली हाईस्कूल की 28 बालिकाओं को मिली निशुल्क सरस्वती साइकिल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

चांदनी बिहारपुर। क्षेत्र के शासकीय हाईस्कूल महुली में शासन की सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं में नवप्रवेशी बालिकाओं एवं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पन्डो जनजाति के बालक को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जय बाबू जायसवाल, सरपंच रनसाय खेरवार, उपसरपंच पहलवान खेरवार, बैकुंठ प्रसाद जायसवाल, पूनम चंद गोयल, मदन लाल जायसवाल आदि उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को साइकिल प्रदान की गई।

विद्यालय के प्राचार्य रामशरण प्रजापति ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सरस्वती साइकिल योजना का उद्देश्य छात्राओं को विद्यालय आने जाने में सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि दूरी के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और बालिकाएं नियमित रूप से विद्यालय पहुंचकर अपनी शिक्षा जारी रख सकें।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने छात्राओं को साइकिल का सदुपयोग करते हुए नियमित रूप से विद्यालय आने तथा मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बालिकाओं के भविष्य को बेहतर बनाने का सबसे मजबूत माध्यम है। शासन द्वारा छात्राओं को स्कूल तक पहुंचने में सुविधा देने के लिए संचालित ऐसी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को विशेष लाभ मिल रहा है।इस अवसर पर शाला प्रबंधन समिति के सदस्य रामलल्लू देवांगन, बृजेंद्र शर्मा, फूल कुंवर, शिक्षक वीरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश साहू, आशा प्रजापति एवं सविता साहू सहित समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएं, शाला प्रबंधन समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथियों एवं उपस्थित ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया गया।

राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की कार्यशाला में शिक्षकों को मिली विज्ञान एवं नवाचार परियोजनाओं की जानकारी

सतत विकास हेतु विज्ञान एवं नवाचार पर विशेषज्ञों ने दिए व्याख्यान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, रायपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन यहां के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों को विज्ञान आधारित परियोजनाओं, नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना रहा।

कार्यक्रम का शुभारंभ जिले के डीएमसी मनोज साहू एवं सहायक संचालक अजय सिंह ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यशाला सतत विकास के लिए विज्ञान एवं नवाचार विषय पर केंद्रित रही। कार्यशाला को संबोधित करते हुए डीएमसी मनोज साहू ने कहा कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना विज्ञान शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय तेजी से तकनीकी एवं एआई आधारित हो रहा है। ऐसे में विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखते हुए नवाचार और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के नए वैज्ञानिक विचार और नवाचार ही भविष्य में उनके लिए बेहतर करियर के अवसरों का आधार बन सकते हैं।

कार्यशाला में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के पांच प्रमुख उप-विषयों पर विषय विशेषज्ञों ने विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। डॉ. धनंजय पांडे, प्राध्यापक, नवीन कन्या महाविद्यालय ने सतत विकास के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों का अनुप्रयोग विषय पर भारतीय पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय की संभावनाओं पर प्रकाश डाला।

डॉ.ओम प्रकाश, प्राध्यापक, शासकीय वेटरनरी महाविद्यालय सूरजपुर ने जल संचयन, जल का प्रभावी उपयोग, जल पुनर्चक्रण एवं जल संरक्षण विषय पर परियोजना आधारित जानकारी देते हुए जल संकट के समाधान में विद्यार्थियों की भूमिका को रेखांकित किया। इसी क्रम में डॉ. तुलसीराम रहंगडाले, प्राध्यापक, रेवती रमण महाविद्यालय ने खाद्य, कृषि एवं स्वास्थ्य विषय पर वैज्ञानिक परियोजनाओं की संभावनाओं तथा स्थानीय स्तर पर किए जा सकने वाले नवाचारों की जानकारी दी।

डॉ. संदीप सोनी, प्राध्यापक, कन्या महाविद्यालय ने अपशिष्ट प्रबंधन कम करना, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनः डिजाइन एवं पुनर्चक्रण विषय पर प्रकाश डालते हुए कचरा प्रबंधन को लेकर नवीन एवं उपयोगी परियोजनाओं की संभावनाओं को समझाया। वहीं संतोष कुमार उपाध्याय, व्याख्याता, शासकीय हाई स्कूल लक्ष्मीपुर ने ऊर्जा—अन्वेषण, प्रयोग, सुधार एवं विकास विषय पर विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, व्यावहारिक एवं नवाचारपरक परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया समझाई। कार्यशाला में जिले के पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के विज्ञान एवं गणित विषय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। विशेषज्ञों ने पांचों उप-विषयों की मूल अवधारणा, परियोजना के लिए विषय चयन, समस्या की पहचान, वैज्ञानिक पद्धति, नवाचार, आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण तथा परियोजना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2026 में पंजीयन की प्रक्रिया एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों से शिक्षकों को अवगत कराया गया। सभी संबंधित विद्यालयों को 31 दिसंबर तक पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। कार्यशाला के दौरान शिक्षकों ने स्थानीय समस्याओं को केंद्र में रखकर वैज्ञानिक एवं नवाचार आधारित परियोजनाएं विकसित करने में विशेष रुचि दिखाई। जल संरक्षण, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन तथा भारतीय ज्ञान प्रणालियों जैसे विषयों को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़कर परियोजनाओं के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम का सफल संचालन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर शंभू प्रसाद निषाद द्वारा किया गया। कार्यशाला के सफल आयोजन में संस्था की प्राचार्य श्रीमती अनु कांडे, सुनील कुमार पांडे, डॉ. निशा सिंह, दीपक पटेल, दुष्यंत राजवाड़े, गोपाल सिंह, दिनेश प्रजापति एवं आदित्य दुबे का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। समग्र रूप से कार्यशाला शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी रही। कार्यशाला के माध्यम से शिक्षकों को विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा स्थानीय समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान खोजने वाली नवाचारपरक परियोजनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

मोबाइल स्नेचिंग करने वाले नाबालिग समेत दो आरोपी पकड़ाए

रायपुर। राजधानी रायपुर में चोरी की एक्टिवा से मोबाइल स्नेचिंग करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी और विधि के साथ संघर्षरत बालक को पकड़ा है। दोनों के कब्जे से चोरी की एक्टिवा और स्नेचिंग किए गए 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। जब्त सामान की कुल कीमत करीब 1.50 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस के मुताबिक, 19 अगस्त की सुबह सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में मोबाइल स्नेचिंग की दो वारदातें हुई थीं। कोटा निवासी उन्नति ठाकुर दिशा कॉलेज रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रही थीं। इसी दौरान ग्रे रंग की एक्टिवा पर सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उनका

मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। इसी तरह चौबे कॉलोनी निवासी युवराज मेहर का भी कॉलेज जाते समय मोबाइल छीन लिया गया था। दोनों मामलों में सरस्वती नगर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि वारदात में इस्तेमाल एक्टिवा चोरी की है। एक्टिवा क्रमांक सीजी 04 केएस 6757 को 21 जुलाई को मेडिकल कॉलेज पार्किंग से चोरी किया गया था, जिसकी शिकायत मौदहापारा थाने में दर्ज थी।

पुलिस टीम ने घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने एमजी रोड क्षेत्र में घेराबंदी कर चोरी की एक्टिवा पर सवार दो युवकों को पकड़ लिया। पूछताछ में एक आरोपी की पहचान वरुण साहू (23 वर्ष), निवासी रामनगर, त्रिमूर्ति चौक, रायपुर के रूप में हुई, जबकि दूसरा आरोपी विधि के साथ संघर्षरत बालक निकला। पूछताछ में दोनों ने एक्टिवा चोरी करने और इसी वाहन से मोबाइल स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की एक्टिवा के साथ 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अब आरोपियों से जुड़ी अन्य तीन मोबाइल चोरी की घटनाओं की भी जांच कर रही है।

सात दिन में करें आवास स्वीकृति, नहीं तो होगी कार्रवाई

संभागायुक्त ने लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत काम करने कहा

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा एवं छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर सचिव तथा विकसित भारत-जी राम जी के अपर आयुक्त एस. आलोक ने शुक्रवार को संभागायुक्त कार्यालय में विकसित भारत-जी राम जी और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की संभागस्तरीय समीक्षा बैठक ली।

बैठक में योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियां, लंबित प्रकरणों के निराकरण और आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। संभागायुक्त ने सभी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सीईओ को सख्त निर्देश दिए कि शासन की योजनाओं का लाभ हर घर, हर गांव तक पहुंचे। उन्होंने कहा सरगुजा संभाग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। हमारी जिम्मेदारी है कि लक्ष्य के अनुसार शत-प्रतिशत कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय-सीमा में पूरे हों। कार्य में कोताही बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एस. आलोक ने वीबीजीराम के अपूर्ण आवास जल्द पूरा करने और युक्तधारा में प्लान किए गए कार्यों की स्थिति पर जानकारी ली। बोरवेल रिचार्ज, मनरेगा के अपूर्ण कार्य, पीएम आवास के हितग्राहियों को 90 मानव दिवस रोजगार देने की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में उपायुक्त आर.के. खूंटे, सरगुजा जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव, जशपुर सीईओ अभिषेक कुमार, बलरामपुर सीईओ आशुतोष चतुर्वेदी, एमसीबी सीईओ अंकिता सोम, कोरिया सीईओ योगेंद्र श्रीवास सहित सभी जनपदों के सीईओ उपस्थित रहे।

मानव दिवस, जल संरक्षण, आवास पर फोकस

बैठक में विकसित भारत-जी राम जी के तहत जुलाई-अगस्त में सृजित मानव दिवस की समीक्षा हुई। संभागायुक्त ने कहा कि, पिछले वर्ष की तुलना में मानव दिवस कम है, इसे शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विद्यालयों में शौचालय, मुक्तिधाम में प्रतीक्षालय-शेड निर्माण के निर्देश दिए। जल संरक्षण को प्राथमिकता देने के लिए वर्षा जल संरक्षण, भूजल स्तर बढ़ाने और पानी की बर्बादी रोकने वाले कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने को कहा। ग्राम पंचायतों में शत-प्रतिशत कार्यों की स्वीकृति देकर समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

पीएम आवास ग्रामीण की समीक्षा

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, विशेष परियोजना और पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत और पूर्ण आवासों की प्रगति देखी गई। संभागायुक्त ने शेष कार्यों की स्वीकृति 7 दिवस के भीतर करने और अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। प्रथम किस्त के लंबित प्रकरणों और भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा कर जल्द निराकरण करने को कहा। आर-सेटी, आरएमटी के प्रशिक्षण और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। संभागायुक्त ने अच्छा प्रदर्शन करने वालों की सराहना की और कमजोर जिलों को बेहतर करने के लिए प्रेरित किया।

कलेक्टर और एसएसपी ने किया पॉलिटेक्निक-लाईवलीहुड कॉलेज का निरीक्षण

नीट पीजी परीक्षा को लेकर व्यवस्थाएं परखीं, 2 परीक्षा केंद्र में 66 परीक्षार्थी होंगे शामिल

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। आगामी 30 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर अजीत वसंत और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को शासकीय पॉलिटेक्निक और लाईवलीहुड कॉलेज, अंबिकापुर का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने लाईवलीहुड कॉलेज में निर्धारित 2 कंप्यूटर लैब का जायजा लिया। इन लैब में कुल 40 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। वहीं शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी नीट पीजी का दूसरा परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां 2 कक्षों में 26 परीक्षार्थी शामिल होंगे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कंप्यूटर सिस्टम, परीक्षा कक्ष और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर परीक्षा के दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महिला एवं पुरुष शौचालयों की सफाई, फ्रिस्किंग एरिया, प्रवेश-निकासी व्यवस्था और परीक्षा केंद्र परिसर की व्यवस्थाएं भी परखी गईं। कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि परीक्षा के दौरान स्वच्छता और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। परीक्षार्थियों और अभिभावकों के आवागमन को देखते हुए कलेक्टर ने यातायात व्यवस्था, पार्किंग और भीड़ नियंत्रण के इंतजाम करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान आवागमन में किसी प्रकार की बाधा न आए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर राम सिंह ठाकुर, सहायक संचालक ललित कुमार पटेल, प्राचार्य गिरीश गुप्ता, सहायक परियोजना अधिकारी अकरम खान सहित कॉलेज के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण देने के निर्देश

कलेक्टर अजीत वसंत ने परीक्षा के सफल और शांतिपूर्ण संचालन के लिए सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और परीक्षार्थियों की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप रहें और परीक्षार्थियों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं व्यवस्थित परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जाए।

दादी प्रकाशमणि की स्मृति में रक्तदान शिविर कल

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की पुण्य स्मृति में अंबिकापुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा 21 से 25 अगस्त तक भारत और नेपाल में रक्तदान शिविरों की श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में अंबिकापुर का शिविर 23 अगस्त, रविवार को लगेगा। अंबिकापुर सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका ब्रह्माकुमारी विद्या ने बताया कि शिविर चोपड़ा पारा स्थित श्नव विश्व भवन में सुबह 9 बजे से संध्या 6 बजे तक आयोजित होगा। यह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आम नागरिकों के लिए खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि दादी प्रकाशमणि का संपूर्ण जीवन नि:स्वार्थ सेवा, प्रेम और विश्व बंधुत्व को समर्पित रहा। उनकी स्मृति में आयोजित यह शिविर पीड़ित मानवता की सेवा का एक पावन प्रयास है। रक्तदान केवल शारीरिक दान नहीं, बल्कि किसी को नया जीवन देने का पुण्य कर्म है। दुर्घटनाओं, आपातकाल और गंभीर बीमारियों में मरीजों के लिए हमारा दिया गया रक्त जीवनदायिनी संजीवनी बनता है। उन्होंने बताया कि शिविर में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सकों की टीम सभी रक्तदाताओं का प्राथमिक स्वास्थ्य जांच करेगी। रक्तदान के बाद सभी को जलपान कराया जाएगा और संस्था की ओर से प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित भी किया जाएगा।

सभी वर्ग से भागीदारी की अपील

ब्रह्माकुमारीज संस्थान ने शहर के सामाजिक संगठनों, युवाओं, प्रबुद्ध नागरिकों और धर्मप्रेमियों से अपील की है कि, वे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पुण्य कार्य में सहयोग करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें।

संत गहिरा गुरु के 600 से अधिक उपासक 120 किमी पदयात्रा पर रवाना

सावन नवमी पर छोटा तुर्रा से उठा पवित्र जल, तेरस को कैलाश गुफा में जलाभिषेक

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर। संत गहिरा गुरु के उपासकों की आस्था से जुड़ी ऐतिहासिक पदयात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा के साथ शुरू हो गई है। सावन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर छोटा तुर्रा, रामगढ़ से पवित्र जल उठाने के बाद 600 से अधिक कांवरिये 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर कैलाश गुफा के लिए रवाना हो गए हैं। कांवरियों की यह संख्या अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। कांवरियों का जत्था छोटा तुर्रा से जल लेकर उदयपुर, लखनपुर, मेंड्रऊ, कंठी, रघुनाथपुर, झेराडीह और सामरबार होते हुए कैलाश गुफा पहुंचेगा। इस दौरान कांवरियों को करीब तीन दिन पैदल चलना होगा। यात्रा के चैथे दिन तेरस तिथि को कैलाश गुफा पहुंचकर भगवान शिव के शिवलिंग में पवित्र जल अर्पित कर जलाभिषेक किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान उदयपुर पहुंचने पर कांवरियों के लिए अग्रवाल समाज की ओर से सामुदायिक भवन में जलपान की व्यवस्था की गई। समाज के सदस्यों ने कांवरियों का स्वागत कर यात्रा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई।

कांवरियों के रवाना होने से पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल है।

वर्षों पुरानी परंपरा-संत गहिरा गुरु के अनुयायियों द्वारा कैलाश गुफा में जलाभिषेक की यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। हर वर्ष सावन शुक्ल पक्ष की नवमी को छोटा तुर्रा से जल उठाया जाता है और तेरस को कैलाश गुफा में जलाभिषेक होता है। श्रद्धालु पूरी यात्रा के दौरान धार्मिक अनुशासन और भोलेनाथ के जयकारों के साथ चलते हैं। यात्रा को सफल बनाने में संत गहिरा गुरु के छोटे पुत्र गेंद बिहारी सिंह, गोविंद सिंह अंधला, कैलाश कंदराई, जय प्रकाश और गंवटिया पलका सहित अन्य सहयोगी सक्रिय हैं। कांवरियों की संख्या बढ़ने से व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरगुजा में हुए 2 दोहरे हत्याकांड में शामिल 2 आरोपी जेल दाखिल

छ.ग.फ्रंटलाइन कमलेश्वरपुर। सरगुजा में हुए दो दोहरे हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल दाखिल कर दिया है। थाना कमलेश्वरपुर पुलिस ने ग्राम बिसरपानी दारापारा में हुए दोहरे हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में युवक के साथ देखा था, इससे कुपित होकर वह अपनी पत्नी और युवक की फावड़ा से मारकर हत्या कर दिया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी एवं एसडीओपी सीतापुर तुल सिंह पट्टावी के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार प्रजापति की टीम को आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। पुलिस के अनुसार, 17 अगस्त की शाम ग्राम बिसरपानी दारापारा निवासी सोमारू मझवार के घर मृतक बेंजे बड़ा 35 वर्ष, मृतिका नईहारो मझवार 32 वर्ष और नईहारो का पति बाबुलाल मझवार 35 वर्ष शराब के नशे में आए थे। तीनों आग ताप रहे थे इसी दौरान आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद सोमारू दूसरे घर में चले गया। 18 अगस्त की सुबह सोमारू आया तो बेंजे बड़ा और नईहारो मझवार घर के

अंदर खून से लथपथ मृत पड़े थे, बाबुलाल नहीं था। पुलिस जांच में पता चला कि बाबुलाल ने की चरित्र शंका को लेकर फावड़ा से पत्नी नईहारो और युवक बेंजे की हत्या की है। इसी क्रम में पुलिस ने संदेही बाबुलाल मझवार पिता बुधु मझवार, निवासी बिसरपानी तिलकपारा को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा और घटना के दौरान पहने कपड़े जप्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। टीम में एएसआई बैजनाथ राम, एएसआई बबलू कुजूर, सायबर प्रभारी अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, आरक्षक विकास मिश्रा, अशोक यादव, अर्जुन पैकरा, बरन सिंह शामिल रहे।

सब्जी नहीं बनाने से नाराज होकर माता-पिता की हत्या करने वाला पुत्र गिरफ्तार

धौरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सपड़ा परसापारा में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की मां ने खाने में सब्जी नहीं बनाया था, इसी विवाद के चलते वह अपने माता-पिता की टांगी से हत्या कर दोनों शवों को प्लास्टिक बोरा में लपेट दिया था। घटना 16 अगस्त रात की है।

ग्राम सपड़ा निवासी मोहन यादव ने पुलिस को घटना की सूचना दी थी कि पुराने घर के एक कमरे में उसके पिता हीराधर यादव और मां गुलाबी यादव का शव प्लास्टिक बोरा में रस्सी से बंधा हुआ पड़ा है। घर के दरवाजे में ताला लगा था और कमरे की जमीन पर खून के निशान व ताजा गोबर से लिपाई की गई थी। उसने बड़े भाई जदू यादव पर संदेह जाहिर किया था। मामले में अपराध दर्ज करके पुलिस ने संदेही जदू यादव पिता हीराधर यादव 36 वर्ष, को हिरासत में लिया तो उसने 16 अगस्त की रात आपसी विवाद होने पर टांगी से अपने माता-पिता की हत्या करना स्वीकार किया। हत्या के बाद दोनों के शव को प्लास्टिक बोरा में लपेटकर कमरे में रख दिया और फरार हो गया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त टांगी और कपड़ा जप्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कार्रवाई टीम में एएसआई राम धनी राम, सायबर सेल प्रभारी एएसआई अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, बलबीर मिंज, महिला आरक्षक ज्योति पैकरा, आरक्षक पंकज देवांगन, अशोक यादव, हरिकिशुन, देव सिंह, बसंत, अभिषेक, सुशील मिंज सक्रिय रहे।

संभाग स्तरीय रेड रन मैराथन, युवाओं को दिया स्वास्थ्य और एड्स जागरूकता का संदेश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को सरगुजा संभाग स्तरीय रेड रन मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन पी.जी. कॉलेज खेल मैदान में किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाषनगर ने किया। आयोजन राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. नीता बाजपेयी के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, नियमित व्यायाम की आदत, नशे से दूर रहने की भावना विकसित करना और एचआईवी/एड्स के प्रति जन-जागरूकता फैलाना था। मैराथन को मुख्य अतिथि राज्य एड्स नियंत्रण समिति की संयुक्त निर्देशक डॉ. सृष्टि भाग्यश्री वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. एस.एन. पाण्डेय, कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो. संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जिला अस्पताल से डॉ. सरगेश यादव, खेमकरण अहिरवार, दीवान, शुभम गुप्ता, जॉन पीटर टोप्पो, राहुल नीरज, अशोक एक्का एवं धीरज कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।

बालक-बालिका वर्ग में 100 से अधिक प्रतिभागी

संभाग के विभिन्न महाविद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने स्वस्थ युवा-स्वस्थ समाज, नशे से दूर रहें और एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक रहें, के बैनर और नारे के साथ संदेश दिया। बालक और बालिका वर्ग की दौड़ अलग-अलग कराई गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों ने युवाओं को नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया।

ये रहे विजेता-बालिका वर्ग में प्रथम पूर्णिमा मांझी, द्वितीय जवारो, तृतीय इंदुमति नायक, चतुर्थ वर्षा कुजूर, पंचम बिन्दु यादव, बालक वर्ग में प्रथम मनीष विश्वास, द्वितीय हरिओमप्रकाश राजवाड़े, तृतीय कर्मा सन्याशी, चतुर्थ तेज सिंह, पंचम आशीष बड़ा रहे। आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों, अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

नाबालिग और युवती को दिल्ली ले जाते दो मानव तस्कर रायगढ़ में पकड़ाए

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले केरजू क्षेत्र से नाबालिग छात्रा और एक युवती को दिल्ली में अच्छी नौकरी और वेतन का झांसा देकर ले जा रहे दो मानव तस्करों को रायगढ़ में गिरफ्तार किया गया है। परिजनों की सतर्कता से यह मामला खुला।

पुलिस के अनुसार, केरजू क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा और एक युवती को रायगढ़ जिले के दो युवकों विद्याभूषण लकड़ा निवासी सिहारजोर और देवलाल तिग्गा निवासी कमोसिनडांड कापू ने दिल्ली में अच्छे पगार पर काम दिलाने का झांसा दिया। दोनों के कहने पर नाबालिग और युवती बिना किसी को बताए घर से निकलकर उनके साथ चले गए। परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने नाबालिग और युवती की तलाश शुरू की। तलाश के दौरान परिजनों ने दोनों युवतियों को युवकों के साथ रायगढ़ में पकड़ लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी और अपहरण का मामला दर्ज किया है। थाना में धारा 137(2), 143(1)(क), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने नाबालिग और युवती को प्रलोभन देकर बाहर ले जाने की बात स्वीकार की है।

पुलिस-अस्पताल के बीच रिपोर्टिंग होगी तेज, चिकित्सकों को दिया गया प्रशिक्षण

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पुलिस और चिकित्सा विभाग के बीच समन्वय बढ़ाने एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में मेडिको लीगल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग एवं सीसीटीएनएस माड्यूल पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया।डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस शिविर में जिले के विभिन्न शासकीय अस्पतालों में पदस्थ 19 डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी, डॉ. संटू बाघ, डॉ. रवि किरण तिर्की, आरक्षक प्रदीप केरकेट्टा एवं महिला आरक्षक प्रिया रानी भी उपस्थित रहे।

ऑनलाइन होगी एमएलआर/पीएमआर रिपोर्टिंग-प्रशिक्षण में बताया गया कि एमईडीएलईएपीआर पोर्टल पुलिस और शासकीय अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बनाई गई सुरक्षित ऑनलाइन प्रणाली है। इसके माध्यम से मेडिको-लीगल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऑनलाइन जमा की जा सकेंगी। यह पोर्टल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से एकीकृत है। अब थानों में सीसीटीएनएस के माध्यम से एमएलआर/पीएमआर संबंधित अस्पतालों को एमईडीएलईएपीआर पोर्टल पर भेजी जाएगी। वहीं अस्पताल भी रिपोर्ट तैयार कर सीधे संबंधित थाने के सीसीटीएनएस पर ऑनलाइन भेज देंगे। इससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया में देरी कम होगी।

सटीकता और गोपनीयता पर जोर-डीआईजी/एसएसपी राजेश अग्रवाल ने कहा कि इस नई प्रक्रिया से रिपोर्टिंग में सटीकता बढ़ेगी क्योंकि मैन्युअल त्रुटि की संभावना नहीं रहेगी। साथ ही यह सुरक्षित प्रणाली है जो मेडिकल डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। उन्होंने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे इस प्रक्रिया का पूरी निष्ठा से पालन करें ताकि अस्पताल और थाना के विवेचना अधिकारियों के बीच सहयोग और बेहतर हो सके।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा0प्र0क्र0-.../20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती कुन्ती देवी आ0/पति दिनेश कुमार जाति निवासी केदारपुर, अमिबकापुर, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला-केदारपुर, शीट नम्बर 4 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 1963/6 रकबा 0.04 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अत: उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31.08.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक: 13.08.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

महिला पुलिस के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप कल, आईजी ने जारी किया पत्र

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पुलिस विभाग की महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 23 अगस्त को अंबिकापुर में विशेष ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैम्प का आयोजन किया जाएगा। कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज द्वारा जारी पत्र के अनुसार यह कैम्प भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी अंबिकापुर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सरगुजा शाखा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा। सरगुजा रेंज के सभी अधीनस्थ जिलों में पदस्थ महिला पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के लिए रायपुर से विशेषज्ञ मेडिकल टीम और हाईटेक सुसज्जित मोबाइल मेडिकल वेन अंबिकापुर मुख्यालय पहुंचेगी। इसके माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैम्प लगाया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने जिले से अधिक से अधिक संख्या में महिला अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके परिवार की महिला सदस्यों को इस जांच शिविर में शामिल होने के लिए प्रेरित करें।

पुलिस परिवार को लाभ पहुंचाना ध्येय

आईएमए सरगुजा शाखा के डॉ. अर्पण सिंह ने इस आयोजन को महिला पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य और जागरूकता के क्रम में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने बताया कि, ध्येय के अनुरूप शिविर के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शिविर की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रेड क्रॉस सचिव और रक्षित केंद्र अंबिकापुर के आरआई को भी आगाह कराया गया है, ताकि शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और पुलिस परिवार को इसका लाभ मिले।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दरीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर